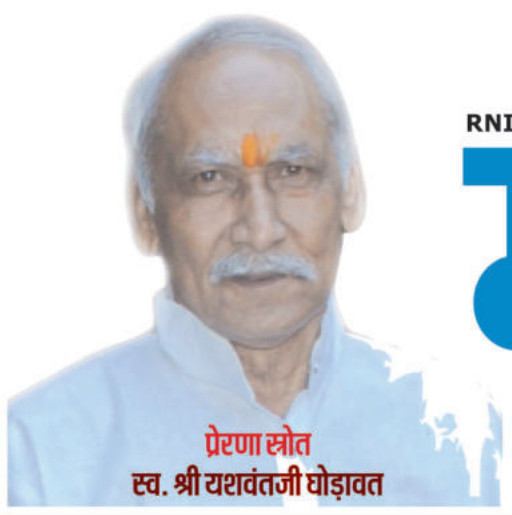


RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

# माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com


**सुविचार**

अगर आप सही राह पर चल रहे हैं, और आप चलते रहने के लिए तत्पर हैं, तो आप अंततः प्रगति करेंगे।

बराक ओबामा


वर्ष-08, अंक - 37 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 02 जुलाई 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए


# असहयोग...उपेक्षा...और विरोध...

# मोहन राज में कई मंत्री दुखी लेकिन मौन

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

**संजय भटेवरा**

*मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है और किसी न किसी वरिष्ठ विधायक या मंत्री का दर्द छलक कर बाहर आ ही जाता है। कुछ दिनों पूर्व रतलाम ग्रामीण से विधायक मथुरा लाल डामर ने सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा जाहिर की कि, मंत्री मुझ जैसे छोटे विधायकों को पहचानते ही नहीं है वे क्षेत्र की समस्या को लेकर मंत्री को पत्र लिखते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है।*

यही नहीं रतलाम में जिला पंचायत अध्यक्ष को कलेक्टर से मिलने के लिए भी धरने पर बैठना पड़ा था। हाल ही में मुख्यमंत्री के परिवार में जमीन खरीद संबंधी मामला सामने आया था। जिसमें कांग्रेस नेताओं का कहना था कि, उन्हें जानकारी एक भाजपा विधायक से ही मिली थी। यही नहीं कैबिनेट की बैठक में भी वरिष्ठ नेताओं में आपसी तनातनी की खबरें बाहर आती रहती है। हालांकि कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष की चिंगारी तो भड़क ही रही है।

हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गी का एक पत्र चर्चा में आया है। जिसमें वे इंदौर की उपेक्षा से नाराज होकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। 20 जून को लिखे पत्र में उन्होंने इंदौर की उपेक्षा, असहयोग और विरोध को लेकर पांच बिंदुओं पर मुख्यमंत्री को अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। जिसमें 2 साल से तैयार मास्टर प्लान के लिए लिखा गया है कि, इंदौर का मास्टर प्लान 2 वर्ष पूर्व आपको भेजा गया था।

विभागीय और सीएम स्तर पर व्यापक चर्चा हो चुकी है परंतु आज तक इसे जारी नहीं किया गया है, पहले भी पत्र लिख चुके हैं लेकिन न तो जवाब दिया गया न ही चर्चा की गई।

दूसरा बिंदु :- मेट्रोपालीटन रीजन में इंदौर का अवमूल्यन को लेकर है। पत्र में लिखा गया है कि इंदौर, प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, मेट्रोपालिटन रीजन की हर चर्चा इंदौर पर केंद्रित रही है। रीजन में इंदौर का हिस्सा उज्जैन से ज्यादा है पर अधिसूचना में इसका नाम उज्जैन-इंदौर मेट्रो पालीटन कर दिया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि को तीन भागों में बांटने के प्रस्ताव में भोपाल, उज्जैन व जबलपुर में इकाई प्रस्तावित है। इंदौर में 1952 स्थापित की गोविंदराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान की अपेक्षा की गई है। इंदौर में 50 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज है फिर भी यह मौका इंदौर को नहीं दिया गया। इसके साथ ही पीथमपुर में 650 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई और 176 से अधिक बड़े कारखाने हैं इसके बाद भी राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन सेंटर लंबे समय से लंबीत है। अपेक्षाकृत नए विक्रमपुरी उज्जैन औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं विकसित की जा रही है वही पीथमपुर उपेक्षित है। यही नहीं विजयवर्गी ने अपने पत्र में इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध न कराने ओर सिंहस्थ के कार्यों में इंदौर की अनदेखी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने भीषण जल संकट के दौर में इंदौर को विशेष राहत न देने पर भी अपना असंतोष जताया है।

उल्लेखनीय है कि, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री भी है और पिछले ढाई वर्षों में मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने मुख्यमंत्री से सहयोग न मिलने व उपेक्षा व विरोध का हवाला दिया है। यही नहीं विभागीय स्थानांतरण में खुद को जानकारी न देने की बात भी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि, इंदौर के विकास की गति बढ़ाना तो दूर बल्कि उसका वाजिब हक भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इंदौर की जनता की आवाज को सार्वजनिक मंचों पर उठाना मेरी मजबूरी होगी।

हालांकि पत्र सार्वजनिक होने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे पार्टी का आंतरिक मामला करार दिया है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर भी नेताओं के बयान वायरल हो रहे। बहरहाल मंत्री जी का कहना है कि, यह पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी की ओर से भी तत्काल डैमेज कंट्रोल की खबर आ रही है। मामला भले ही अभी कुछ समय के लिए शांत हो जाए लेकिन चिंगारी तो जल ही उठी है और अन्य असंतुष्ट नेताओं के लिए भी यह खत अपनी नाराजगी जाहिर करने का कारण हो सकता है।

## मध्यप्रदेश में 20 हजार से अधिक मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस नवीनीकरण लंबित

भोपाल।

मध्यप्रदेश में करीब 20 हजार से अधिक मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस का नवीनीकरण पिछले 11 महीनों से लंबित है। इसके कारण बड़ी संख्या में दवा दुकानें तकनीकी रूप से अनियमित स्थिति में संचालित हो रही हैं। बताया जा रहा है कि परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य किए जाने तथा ऑनलाइन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण हजारों आवेदन लंबित पड़े हैं।

दवा विक्रेताओं का कहना है कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए उन्हें बार-बार संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। नवीनीकरण में देरी से उनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ रहा है और कार्रवाई की आशंका भी बनी हुई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है। दवा कारोबारियों ने शासन से लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने तथा नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग की है, ताकि मेडिकल स्टोर बिना किसी कानूनी बाधा के संचालित हो सकें।

## अमरनाथ यात्राः पंजीकरण शुरू, श्रद्धालुओं में उत्साह

जम्मू।

अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू-कश्मीर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसी क्रम में बुधवार से जम्मू में श्रद्धालुओं के लिए मौके पर पंजीकरण और आरएफआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रक्रिया शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंजीकरण केंद्रों पर पहुंचे, जिससे यात्रा को लेकर उनका उत्साह साफ दिखाई दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

श्रद्धालुओं ने यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं की सराहना की। एक श्रद्धालु ने बताया कि उन्हें पहले जत्थे में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पंजीकरण पूरा होने से वे बेहद उत्साहित हैं। वहीं, कई अनुभवी यात्रियों ने पिछले वर्षों की तुलना में इस बार की व्यवस्थाओं को बेहतर बताया।

कुछ श्रद्धालुओं ने पंजीकरण और आरएफआईडी कार्ड प्राप्त करने में थोड़ी प्रतीक्षा का अनुभव साझा किया, लेकिन उनका कहना था कि, इसके बाद बाबा बर्फानी के दर्शन का विश्वास और संतोष मिलता है।

उधर, पहले जत्थे के रवाना होने से पहले श्रीनगर के पारगमन शिविरों में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। पहली बार यात्रा पर आए कई श्रद्धालु विशेष उत्साह के साथ नजर आए। एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि वह बाबा भोलेनाथ की आस्था से यात्रा पर आई हैं और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी।

## हाईकोर्टः राघव च ा से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश

न ई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें आंशिक राहत प्रदान की है। न्यायालय ने सामाजिक माध्यमों और अन्य डिजिटल मंचों पर प्रसारित पांच आपत्तिजनक दस्तावेज हटाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कथित मानहानिकारक

सामग्री को व्यापक स्तर पर हटाने अथवा व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि जिन पांच दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता ने विशेष आपत्ति जताई है, उन्हें हटाया जाए। वहीं शेष सामग्री प्रथम दृष्टया न तो मानहानिकारक प्रतीत होती है और न ही व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने पहले की सुनवाई में भी मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि मामला व्यक्तित्व अधिकारों की तुलना में राजनीतिक आलोचना से अधिक जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।

न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक नेताओं के निर्णयों की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। ऐसे मामलों में व्यक्तित्व अधिकारों और मानहानि के दावों के बीच अंतर करना आवश्यक है।

याचिका में राघव चड्ढा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार डीपफेक वीडियो, परिवर्तित तस्वीरों, कृत्रिम आवाज की नकल, मनगढ़ंत भाषणों तथा अन्य भ्रामक डिजिटल सामग्री पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायालय को बताया गया कि कुछ तस्वीरों में उन्हें साड़ी पहने हुए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर धन बरसाते हुए दिखाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस प्रकार की सामग्री के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि उन्होंने राजनीतिक लाभ अथवा धन के लिए अपना पक्ष बदल लिया है।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने दलील दी कि संबंधित सामग्री अश्लील, भ्रामक और मानहानिकारक है। वहीं न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक राजनीतिक नेता को आलोचना और व्यक्तिगत हमले के बीच अंतर समझना चाहिए तथा प्रत्येक आलोचनात्मक सामग्री को व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो प्रतिवादियों की पहचान स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में न्यायालय की सहायता के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। फिलहालन्यायालय ने केवल पांच आपत्तिजनक दस्तावेज हटाने के निर्देश दिए हैं और व्यापक अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

## वेनेजुएला में मृत भारतीय नाविक के शव से प्रमुख अंग गायब, जांच की मांग

नई दिल्ली।

वेनेजुएला में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय नाविक राकेश चौहान (33) के शव का भारत पहुंचने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। परिजनों का दावा है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुए पोस्टमार्टम में उनके शरीर से कई प्रमुख आंतरिक अंग अनुपस्थित पाए गए। मामले के सामने आने के बाद मौत के कारणों और संबंधित कंपनी की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

राकेश चौहान मर्चेंट नेवी में मरीन फिटर के रूप में वेनेजुएला में कार्यरत थे। परिजनों के अनुसार, कंपनी ने 7 मई को सूचना दी थी कि वह जहाज पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके अगले दिन उनकी मृत्यु की जानकारी दी गई। कंपनी ने मृत्यु का कारण चक्कर आने के बाद गिरने से हृदयाघात होना बताया था।

परिवार का कहना है कि जब शव भारत पहुंचा तो शरीर पर गर्दन से नीचे तक तथा एक कान से दूसरे कान तक कई टांके लगे हुए थे। परिजनों का आरोप है कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि वेनेजुएला में पहले ही पोस्टमार्टम किया जा चुका था।

देवरिया में जिला प्रशासन के निर्देश पर हुए दूसरे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने दावा किया कि शरीर से मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़े, दोनों गुर्दे, प्लीहा, अग्न्याशय, पित्ताशय, आंतें, मूत्राशय सहित कई प्रमुख आंतरिक अंग नहीं मिले। परिजनों का यह भी कहना है कि विसरा उपलब्ध नहीं था, जिससे मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने में कठिनाई हो सकती है।

फेडरेशन ऑफ सीफेयरर्स यूनियंस ऑफ इंडिया ने भी मामले पर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने सवाल उठाया है कि यदि अंग निकाले गए थे तो परिवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई और आवश्यक सहमति प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि शव प्राप्ति संबंधी दस्तावेजों में कुछ विसंगतियां थीं तथा नियुक्ति और तैनाती से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जानी चाहिए।

राकेश चौहान की पत्नी रंजना चौरसिया अपने छह माह के बेटे के साथ रह रही हैं। परिवार का कहना है कि राकेश को विदेश भेजने में उन्होंने बड़ी राशि खर्च की थी। परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तथा उचित आर्थिक सहायता की मांग की है।

# तमिलनाडुः 15 विधायकों से इस्तीफा दिलवाने की साजिश, तीन गिरफ्तार

चेन्नई।

**तमिलनाडु पुलिस ने सत्तारूढ़ दल टीवीके के विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने की कथित साजिश के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य के खुफिया विभाग के अनुसार, ये लोग टीवीके के 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलवाने की योजना बना रहे थे। बुधवार को पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच में डीएमके के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई वी. अशोक कुमार का नाम भी सामने आया है। दोनों पर इस कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।**

टीवीके के एक विधायक की शिकायत के बाद खुफिया विभाग ने जांच शुरू की और एक परामर्शदाता संस्था के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान अधिकारियों को उसके संबंध डीएमके विधायक एवं पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े होने के संकेत मिले। इसके बाद दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पहला आरोपी चेन्नई से तथा अन्य दो आरोपियों को करूर से गिरफ्तार किया गया। खुफिया विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है।

तमिलनाडु में इस वर्ष मई में हुए विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय की पार्टी तमिल वेत्री कड़गम को 108 सीटों पर जीत मिली थी। विजय ने दो सीटों पर विजय प्राप्त की थी। राज्य की 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन आवश्यक होता है। एक सीट छोड़ने के बाद विजय को बहुमत के लिए अन्य दलों के समर्थन की आवश्यकता पड़ी थी। कांग्रेस, वामपंथी दलों और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से उन्होंने सदन में बहुमत साबित किया था।

टीवीके विधायक एन. इलायाराजा ने इस मामले में चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आईपीडीएस नामक एक परामर्शदाता संस्था के प्रतिनिधि ने उन्हें तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के बदले 35 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी। विधायक का आरोप है कि उन्हें धमकाते हुए इस प्रस्ताव की जानकारी किसी को न देने के लिए कहा गया था।

टीवीके सरकार में मंत्री निर्मल कुमार ने दावा किया कि कुछ राजनीतिक नेता गुप्त रूप से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके के कुछ नेता टीवीके विधायकों से संपर्क कर उन्हें 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक की पेशकश कर रहे थे।

वहीं डीएमके ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सरकार पर जांच से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर सनसनी फैलाने का आरोप लगाया है। डीएमके प्रवक्ता ए. सरवनन ने कहा कि यदि सरकार के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं तो वह कानूनी कार्रवाई कर इसे साबित करे। सेंथिल बालाजी और मुख्यमंत्री विजय के बीच पहले भी राजनीतिक मतभेद सामने आते रहे हैं।

# रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर पर तीसरी आंख कमजोर, अपराधी उठा रहे फायदा

## मुख्य चौराहे पर हुई चोरी की वारदात में रेलवे स्टेशन पर जीप में सामान भर कर ले गए चोर

रेलवे स्टेशन के बाहर सामान भरते दिखे चोर।

रेलवे स्टेशन का बाहरी परिसर दो कैमरों के भरोसे।

इस तरह तीसरी मंजिल पर लोहे का दरवाजा तोड़ कर दुकान में घुसे चोर।

**माही की गूंज, बामनिया।**

बामनिया रेलवे स्टेशन के निकट स्थित अन्नपूर्णा किराना पर गत गुरुवार की रात्रि दो लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस को 8 दिन बाद भी कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन चोरी की वारदात में ऐसा घटनाक्रम सामने आया कि जानकर सब चौंक गए। चोरी में बाकायदा रेकी कर वारदात को अंजाम देना प्रतीत होता है। चोरों ने चोरी का सामान ले जाने के लिए बोलेरो जीप का उपयोग किया, जिसे रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कर बेखौफ होकर चोरी का माल वाहन में भरकर रफूचक्कर हो गए। रामेश्वर गर्ग की दुकान के पीछे वाले हिस्से में रेलवे कॉलोनी लगी हुई है। उसी हिस्से से चोरों ने रामेश्वर गर्ग की दुकान को निशाना बनाते हुए पीछे तीसरी मंजिल पर चढ़कर दरवाजा तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और दुकान में रखा सामान सिगरेट, पाउच, बीड़ी, काजू, बादाम, केसर, तेल व अन्य सामान के साथ दस हजार रुपए नगदी पर हाथ साफ कर दिया। दुकान में कैमरे भी लगे थे, लेकिन शातिर चोरों ने कैमरे की डीवीआर तोड़ दी और काउंटर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे, जो वाई-फाई से चल रहे थे, उनको घुमा दिए, ताकि उनके चेहरे कैमरे में कैद न हों। चोरों के लाख प्रयास के बाद भी एक चोर कुछ सेकंड के लिए कैमरे में कैद हो गया है। उसी से अब पुलिस चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

### 24 घंटे चालू रहती है रेलवे की दुकान, वहीं सामान भरते दिखे चोर

रेलवे स्टेशन पर एक दुकान 24 घंटे चालू रहती है। संदिग्ध वाहन और संदिग्ध लोग ठीक इस दुकान के सामने बोलेरो वाहन खड़े दिखे। कयास लगाया जा रहा है कि ये चोर ही थे, जो बेखौफ होकर चोरी का सामान भरते रहे। सामान भरते समय चोर ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे कि वे रेलवे के ही लोग हैं और अपना सामान भरकर ले जा रहे हैं। फिर भी दुकान पर बैठे व्यक्ति ने दूर से चोरों को सामान भरते हुए फोटो खींचा, लेकिन अंधेरा होने के कारण चोरों की पहचान नहीं हो पाई, न ही वाहन के नंबर दिखे। चोर वाहन में सामान भरकर खवासा की ओर रवाना हुए। खवासा में कुछ कैमरे चेक किए गए, लेकिन चोर मुख्य मार्ग की बजाय दूसरे मार्ग से निकल गए।

### तीसरी आंख की कमी

रतलाम-दाहोद के बीच बामनिया एक मुख्य रेलवे स्टेशन है, जहां से हजारों लोगों का रोज आना-जाना होता है। आए दिन रेलवे स्टेशन और उसके आसपास कुछ न कुछ घटना-दुर्घटना होती रहती है। यहां रेलवे स्टेशन के अंदर तो बड़े कैमरे लगे हैं, जिससे अंदर के परिसर पर पूरी नजर रखी जा रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म के बाहर सुरक्षा के नाम पर दो से तीन कैमरे लगे हैं, जो प्लेटफॉर्म तक भी कवर नहीं करते। पिछले दिनों रेलवे स्टेशन के पास दो हत्याएं हो चुकी हैं, जिनको ट्रेस करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि रेलवे स्टेशन के बाहर के परिसर पर कैमरों की कमी है और वारदात को अंजाम देने वाले कैमरों की नजर से बचने में कामयाब भी रहे। चोरी की वारदात में भी चोरों को पता था कि, रेलवे के कैमरे कहां लगे हैं, इसलिए चोरी का सामान भरने के लिए वाहन रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की वाले क्षेत्र में खड़ा किया। ग्राम पंचायत बामनिया की सरपंच रामकन्या मखोड़ ने बताया कि, हमने मुख्य चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन रेलवे की ओर से आने-जाने वाले अपराधियों या किसी भी घटना पर नजर रखने के लिए रेलवे परिसर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की जरूरत है, जिसके लिए वे डीआरएम से मांग करेंगे।

### रेलवे पुलिस नदारद

चोरी की वारदात को रात 12 से 1 बजे के बीच अंजाम दिया गया। वाहन रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया गया। ठीक सामने रेलवे की एक दुकान 24 घंटे चालू थी। वारदात के समय स्टेशन पर लोकल ट्रेनों के आने-जाने का भी समय था। दुकान पर बैठे व्यक्ति को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने चोरों को रेलवे का कर्मचारी समझकर कोई सवाल नहीं पूछा, न ही रेलवे पुलिस को सूचना दी। वाहन काफी देर तक खड़ा रहा, चोरी हुई, सामान लोड हुआ, लेकिन इस दौरान रेलवे पुलिस को कहीं कोई भनक नहीं लगी, न ही रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर आती-जाती दिखाई दी। रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि, हत्या जैसे जुर्म रेलवे स्टेशन के बाहर हो गए, लेकिन रेलवे ने पुलिस व्यवस्था या सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था में सुधार नहीं किया।

# पूर्व मुख्यमंत्री का किया स्वागत

**माही की गूंज, पेटलावद।**

पेटलावद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का झाबुआ दौरे को लेकर भव्य स्वागत किया। शनिवार को पेटलावद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली कि, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का झाबुआ दौरा है और झाबुआ के सर्किट हाउस पर विश्राम करेंगे। यह जानकारी मिलते ही कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के स्वागत के लिए रात्रि में पेटलावद से झाबुआ के सर्किट हाउस पर पहुंच गए। रात्रि में जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सर्किट हाउस पर पहुंचे, उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकमल मालू डामर भी थे। जैसे ही वे झाबुआ के सर्किट हाउस पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दिग्गी राजा जिंदाबाद, कांतिलाल भूरिया जिंदाबाद, वीर सिंह भूरिया जिंदाबाद, अकमल मालू डामर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिग्विजय सिंह का स्वागत किया। वहीं पेटलावद व तहसील के सभी कार्यकर्ताओं से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं व जिले के सभी नेताओं से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन भी किया।

कार्यक्रम में पेटलावद कांग्रेस के नेता, नगर के जुझारू युवा नेता, ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष जीवन ठाकुर ने बताया कि, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से हमारी वन-टू-वन चर्चा हुई, जिससे हम काफी खुश हुए हैं। हमारे द्वारा उनसे मांग भी रखी कि अगली बार जब भी आप जिले में आएं तो पेटलावद होकर गुजरें, जिससे हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी आपसे मिल सकें और आपका स्वागत कर सकें।

सर्किट हाउस, झाबुआ में जिला अध्यक्ष प्रकाश राका, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया, पेटलावद के पूर्व विधायक वाल सिंह मेड़ा के साथ झाबुआ जिले के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण भी मौजूद थे। पेटलावद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष बब्बू काग, गोलू हमाड, विक्रम चावड़ा, नरेंद्र अंजना, रघुनंदन सतोगिया, नाना गोयल, गौरव जानी, जगदीश जानी, प्रभात श्रीवास्तव, कचरु आजना, कैलाश भूरिया, देवेन्द्र सोलंकी के साथ पेटलावद तहसील के ग्रामीण भी मौजूद थे।

# पूज्य श्री चंद्रेशमुनिजी आदि ठाणा का हुआ मंगल प्रवेश

**माही की गूंज, थांदला।**

धर्म नगरी थांदला में एक बार फिर जिन शासन के जयकारों से गगन गुंजायमान हो गया। प्रसंग था जैनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री उमेशमुनिजी म.सा. के अंतेवासी शिष्य पूज्य श्री चंद्रेशमुनिजी, रत्नपुरी गौरव पूज्य श्री पावनमुनिजी संग थांदला गौरव पूज्य श्री जिनांशमुनिजी के थांदला मंगल प्रवेश का। थांदला विराजित महासती पूज्या श्री निखिलशीलाजी के निर्देश पर पूज्या श्री प्रियशीलाजी व पूज्या श्री दीप्तिश्रीजी म.सा. सहित थांदला श्रीसंघ के श्रावक-श्राविकाओं का जन समूह मुनिवृन्द की अगवानी में पेटलावद मार्ग कि ओर पहुँचा व महापुरुषों, गुरुभगवंतों आदि के जयकारों के साथ उनका थांदला में मंगल प्रवेश करवाया। मंगल प्रवेश कि शुभ वेला व पक्खी के पावन प्रसंग होने पर स्थानीय पौषध भवन पर धर्म सभा का आयोजन हुआ जिसे सम्बोधित करते हुए पूज्य श्री चंद्रेशमुनिजी ने कहा कि, व्यक्ति को सुख व दुख में सुख मंगल लगता है लेकिन जिसके गर्त में दुःख छुपा हो जो भविष्य में दुःख का कारक हो वह भी अमंगल ही होता है। पूज्यश्री ने विभिन्न दृष्टांत व स्तवन के माध्यम से सुख के लिए एक मात्र पाप रहित धर्म के मार्ग को प्रमुख बताया। आपने कहा कि जीव अनुत्तर श्रद्धा से स्वयं पर अनुकम्पा करते हुए पाप से विमुख होकर मोक्ष रूपी संवेग को प्राप्त करता है। जबकि इसके विपरीत असंयमी जीव की हर प्रवृत्ति विषय, कषाय को बढ़ाने वाली विकथओं कि ओर ले जाने वाली ही होती है जो भविष्य में उसे दुखी बनाती है। पूज्य श्री ने कहा धन कि भुख ही इसकी जिम्मेदार है जब व्यक्ति में पाप भीरुता आती है व धर्म पर अनुत्तर श्रद्धा होती है तब उसमें धर्म की भूख जगती है और वह उसे सुखी बना देती है। आपने मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताते हुए कहा कि, चारों गतियों में एक मात्र मनुष्य भव ही है जो अनुत्तर श्रद्धा को प्राप्त कर उसे पूर्णतः आचरण में परिवर्तित कर सकता है। धर्म सभा की शुरुआत में थांदला गौरव पूज्य श्री जिनांशमुनिजी ने कहा इस पंचम आरे में सुख की कल्पना करना ही मूर्खता है। आपने धर्म सभा में उपस्थित युवा प्रौढ़ श्रावक-श्राविकाओं से कहा कि आप अपने जीवन में संसार का एक प्रसंग ऐसा बताओं जिसे आप सुख का नाम दे सकते हो, परन्तु आप भी जानते हो संसार में सुख नही है इसलिए सुख प्रसंग बताने का साहस भी किसी में नही है लेकिन इसके विपरीत मुझसे पुछों संयम के सुख के अनेक प्रसंग मेरे जीवन में उपस्थित है। आपने जीवन में तार-तार होते सांसारिक रिश्तों के उदाहरण देकर वर्तमान में खत्म हो चुकी इंसानियत को परिभाषित किया। उल्लेखनीय है कि, धर्मदासगण नायक पूज्य प्रवर्तक श्री जिनेन्द्रमुनिजी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए पूज्य श्री चंद्रेशमुनिजी आदि सभी संतों का अगला वर्षावास गुजरात के लिमखेड़ा में होगा जो पूज्य गुरुदेव का पहला स्वतंत्र वर्षावास होकर उनका गृह नगर भी है।

### तपस्वियों ने किए प्रत्याख्यान ग्रहण

जानकारी देते हुए संघ अध्यक्ष प्रदीप गादियाने बताया कि, पक्खी पर्व के पावन प्रसंग पर पक्खी मण्डल के अराधकों संग नगर में चल रहे सामुहिक वर्षितप अराधकों व अन्य तपस्वियों ने पूज्य गुरुदेव से उपवास, आयम्बिल, निवि, एकासन आदि तप के प्रत्याख्यान ग्रहण किये। सभा का संचालन कर रहे संघ सचिव हितेश शाहजी ने पूज्य गुरुदेव के पूर्व में किये वर्षावास की स्मृति ताजा करते हुए उनके उपकारों को याद करते हुए कुछ दिन स्थिरता की विनंती की।

## 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को सड़क के किनारे स्टॉल लगाकर पिलाई पोलियो की दवा

**माही की गूंज, बरवेट।** बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ चलते-फिरते उप स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। जहां पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाई गई। समाजसेवी अशोक त्रिवेदी, नवलसिंह निनामा ने दो बूंद पोलियो की दवाई पिलाकर आयोजन की शुरुआत की। इस अवसर पर एएनएम बेशम चौहान, सीएचओ ज्योति चौहान, आशा कार्यकर्ता बबली बामनिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लीला मालवीय सहित सभी कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एमएल चोपड़ा के आदेशानुसार राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 28 से 30 जून तक व्यापक स्तर पर अभियान संचालित किया गया। बच्चों को पोलियो रोधी दवा की दो बूंद पिलाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। उप स्वास्थ्य केंद्र बरवेट की एएनएम बेशम चौहान ने बताया कि, अभियान के तहत 0 से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए दवा पिलाई गई। सीएचओ ज्योति चौहान ने बताया कि, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। पोलियो की दो बूंद दवा पिलाकर उन्हें इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा गया। गौरतलब है कि बरवेट में उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर होने से एक दशक से चलता-फिरता उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है। वर्तमान में स्कूल के एक कक्ष में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित किया जा रहा है। जहां पर सुविधाओं के नाम से कुछ भी नहीं है, जिससे प्राथमिक उपचार के लिए मरीजों को अन्य सेंटर पर जाने को मजबूर होना पड़ता है।


## एजेंसी देना है

झाबुआ जिले के मेघनगर, राणापुर , पिटोल, झकनावदा, परवलिया में माही की गूंज की एजेंसी देना है। अन्य स्थान पर जहाँ एजेंसी नही है वहा से भी संपर्क कर सकते है। पत्रकारिता में रुचि रखने व समाचार पत्र का संचालन करने में सक्षम व्यक्ति संपर्क करे।

संपर्क :- संजय भटेवरा प्रधान संपादक माही की गूंज, बाजना मार्ग, खवासा। 9589882798


# गांव में आया स्कूल के लिए अतिरिक्त कक्ष डेढ़ साल बाद भी अधूरा...

## निर्माण एजेंसी व ठेकेदार मौके से गायब, बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़

**माही की गूंज, खवासा।**

ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग झाबुआ, सब डिवीजन थांदला जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत धूमडिया में करीब 5 लाख की लागत से स्कूल के लिए एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में ठेकेदार ने सिर्फ कुर्सी लेवल तक का कार्य किया, उसके बाद ठेकेदार और निर्माण एजेंसी दोनों गायब हैं। ग्रामीणों का कहना है कि, सरकार ने अगर यहां अतिरिक्त कक्ष का निर्माण बच्चों के भविष्य को देखते हुए नया बनाने का प्रस्ताव रखा है, तो इसका पूर्ण निर्माण होना चाहिए, न कि इस तरह की लेट-लतीफी कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। लेकिन यहां देखने वाला कोई नहीं है। निर्माण एजेंसी आरईएस व ठेकेदार मिलकर भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। डेढ़ साल बाद भी आज भवन अधूरा है। यह विचारणीय प्रश्न है ? जिसकी जिम्मेदारी मॉनिटरिंग करने की है, वह सब इंजीनियर भी मौके पर नदारद दिखाई देते हैं।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारीनुसार धूमड़िया के भूरी घाटी फलिया में शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण 18 दिसम्बर 2024 में स्वीकृत हुआ था। लेकिन आज दिन तक इसको पूर्ण नहीं किया गया। कार्य करने का ठेका नव्या ट्रेडर्स को मिला था, जो भिंड के ठेकेदार गोविंद सिंह को कार्य करना था। लेकिन समय गुजर जाने के बाद अभी तक भी वहां निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण वहां के ग्रामीणों के बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों की मांग है कि, जल्द से जल्द भवन का जो कार्य बाकी है, उसका निर्माण किया जाए, ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई समस्या न हो। वहीं, इतने समय से अगर कार्य लेट था, तो विभागीय अधिकारियों ने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की, इसकी भी वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच करें और जो भी दोषी हो, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। यह मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। ठेकेदार ने जब पहली मर्तबा कार्य किया था, तो उसमें भी समय पर तराई नहीं की गई थी, जिससे कहीं न कहीं भवन के कार्य में लापरवाही भी बरती गई है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह ग्रामीणों की मांग है।

वहीं, मामले में नव्या ट्रेडर्स भिंड के ठेकेदार गोविंद सिंह से जब माही की गूंज ने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि साहब, पैसे नहीं हैं। मैं कार्य कैसे करूं? मैंने जल जीवन मिशन के तहत कार्य अलीराजपुर में किया था। वहां 12 लाख रुपए मेरे रुके हुए हैं। अभी मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं वहां कार्य कैसे करूं। मेरे पास जो पैसा था, वह मैंने जल जीवन मिशन में लगा दिया। अब मेरे पास पैसे आएंगे, तभी कार्य करूंगा।

वहीं, मामले में ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग प्रभारी ईई अलावा जी से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि, वहां वास्तव में कार्य बंद है। ठेकेदार व संबंधित इंजीनियर को तलब करने के बाद वहां जल्द ही कार्य शुरू करवाया जाएगा। यह कहकर ईई साहब ने पल्ला झाड़ लिया।

# अखबार की प्रति लहराते हुए सचिव ने दी आत्महत्या की धमकी

## अवैध पट्टे का मामला सामने आने के बाद बौखलाया सचिव, सचिव के विरूद्ध दर्ज करवाई शिकायत

**माही की गूंज, पेटलावद।**

*सारंगी अवैध पट्टा वितरण मामले में एक ओर ग्राम पंचायत की सरपंच फूनदी बाई सफाई देते फिर रही हैं। वहीं सचिव महोदय तो कार्रवाई के डर से अपनी हद ही पार कर गए। जब मामले की शिकायत कर अवैध पट्टे का भांडा फोड़ गांव के ही सोलह शिकायतकर्ताओं ने किया तो ग्राम पंचायत के पेरों तले जमीन खिसक गई। शिकायकर्ताओं को समझाने के सारे प्रयास विफल होने के बाद सचिव ने शिकायकर्ताओं को धमकाने के लिए अलग ही पेतरा आजमाया ओर आत्महत्या की धमकी देकर डराने की कोशिश की।*

### चौकी पर दिया आवेदन

अवैध पट्टे के नाम पर 82 लाख की ठगी की शिकायत करने वाले 16 पीड़ितों ने सारंगी चौकी पर

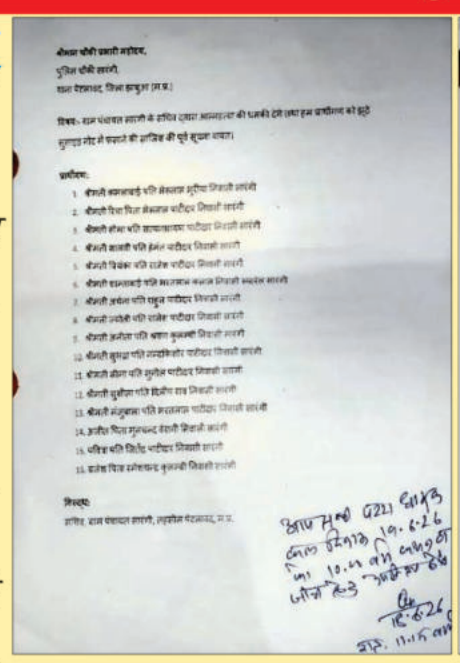

लिखित आवेदन पेश करते हुए ग्राम पंचायत सारंगी के सचिव के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई हैं। 16 शिकायतकर्ताओं ने पुलिस चौकी सारंगी में शिकायत करते हुए बताया कि, अवैध पट्टे देकर 82 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को हमने की थी जिसमें पंचायत समन्वयक रामरतन कवर जांच के लिए आए ओर हम शिकायतकर्ताओं के कथन लिए। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव ओर सरपंच के भी कथन लिए। जिसके बाद ग्राम पंचायत सचिव गांव के ही राकेश बंबोरी की दुकान पर जा कर माही की गूंज अखबार की प्रति लहराते हुए कहा कि, मुझ पर कोई कार्रवाई हुई तो में आत्महत्या कर लूंगा और नाम सभी शिकायतकर्ताओं के लिख कर जाऊंगा। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि, सचिव द्वारा इस तरह की धमकी देकर हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।

### हमारी जिम्मेदारी नहीं

शिकायतकर्ताओं ने आवेदन में साफ लिख कर दिया कि, सचिव इस तरह से धमकी देकर हमको ब्लेकमैल कर रहा है। जबकि हम शांतिपूर्ण ढंग से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ग्राम पंचायत सचिव उसके द्वारा दी जा रही धमकी के हिसाब से कोई कदम उठाता है तो उसकी जवाबदारी हम शिकायतकर्ताओं की ओर राकेश बंबोरी की नहीं रहेगी। शिकायतकर्ताओं ने मामले में आत्महत्या की धमकी देने वाले सचिव पर कार्यवाही की मांग की है।

### कार्रवाई का इंतजार

ग्राम पंचायत सारंगी में सामने आया फर्जी पट्टा वितरण मामला कोई नया नहीं है, एक साल पहले ही इसकी कब्र खोदना शुरू हो चुकी थी और इसके बाद से ही जिन लोगों को पट्टे मिले थे वो ग्राम पंचायत पर लगातार पट्टे के लिए बताई हुई भूमि पर कब्जा देने का दबाओ बना रहे थे। ओर जमीन बताने के बाद कब्जे की कोशिश शुरू हो गई जिसे अतिक्रमण बता कर राजस्व विभाग ने हटा दिया था। गांव के ही 16 लोगों ने शिकायत कर सरपंच,सचिव ओर उप सरपंच के विरुद्ध 82लाख एक मुश्त लेकर 16 पट्टे देने की शिकायत की थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है ओर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसको लेकर शिकायकर्ताओं का कहना है कि, अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी शिकायत आगे भी जारी रहेगी।

# फिर कुएं में उतरी पुलिस की जांच टीम, कुप का पानी खाली कर की खोजबीन

**माही की गूंज, पेटलावद।**

विगत दिनों ग्राम करडावद के देवर-भाभी के शव करवड़ क्षेत्र के एक गांव के कुएं में से बरामद हुए थे। कयास लगाए जा रहे है कि, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और दोनों ने साथ में आत्महत्या कर ली थी। दूसरी ओर मृतका के परिवार वालो ने आत्महत्या वाली थ्योरी पर सवाल खड़े करते हुए मामले को संदिग्ध बताते हुए पुलिस को सभी पहलुओं से जांच करने के लिए आवेदन दिया था। दोनों ही मृतकों के पास मोबाइल थे जो पुलिस को अब तक नहीं मिले।

### कुएं में खोजबीन

सोमवार को पुलिस एक बार फिर घटना स्थल पर पहुंची और मौका जांच शुरू की। जिस कुएं से शव बरामद हुए उसका पानी खाली कराकर मृतकों के समान खास कर की मोबाइल की खोजबीन की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को कुएं से दोनों के मोबाइल बरामद नहीं हुए न कोई दूसरी सामग्री मिली। मोबाइल नहीं मिलने से मामला ओर पेचीदा होता नजर आ रहा है। मृतक महिला के गहने गायब होने की भी बात महिला के परिजनों ने थाने में बता कर शंका जाहिर की थी। मृतक महिला के मामा नरेन्द्र प्रजापत ने बताया कि, परिवार से जानकारी मिली है मेरी मृतक भानेज के गहने घर में ही मिले हैं जिसकी जानकारी परिवार वालो ने पुलिस को दी है। जबकि मेरी भानेज घर से निकली उसके तीन दिन बाद मृत मिली ओर उसके अंतिम संस्कार के तीसरे दिन उसके गहने घर से ही मिले? ये अजीब है कि 06 दिनों तक किसी को गहने घर पर होने की जानकारी कैसे नहीं लग? वहीं कुएं से मोबाइल नहीं मिलने के बाद मृतका के मामा नरेंद्र प्रजापत ने एक बार फिर मामले को सन्देहपद होने की बात कही। पुलिस अब भी पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि दोनों की मौत का वास्तविक ओर सही कारण पता चल सके।

# मानसून की देरी ने किसानों को चिंता में डाला

**माही की गूंज, बरवेट।**

मानसून की बेरुखी ओर अभीतक हुई अल्प वर्षा के कारण हाइब्रिड सब्जी उत्पादक किसान के साथ साथ खरीब फसल उत्पादक किसान परेशान हैं। खासकर छोटे किसानों के लिए समस्या खड़ी होती दिख रही है। जिन किसानों खरीब फसल की बारिश के भरोसे की उसके बाद सिंचाई जरूरी है, लेकिन जिस तरह से बारिश की उम्मीद थी, वह नहीं हो पाई है। जिससे बोवनी कर चुके किसानों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। बरवेट क्षेत्र के किसानों ने बुआई मानसून के भरोसे कर दी थी। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार मानसून साथ देगा। दूसरी ओर मौसम विभाग ने भी दावा किया था कि मानसून अच्छा रहेगा, लेकिन मौसम विभाग के दावे के अनुरूप बारिश न होने के कारण किसानों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा असर छोटे और सीमांत किसानों को हो रही है। जिन किसानों ने बारिश के भरोसे बीजों की रोपाई की है। अब उनके खेतो नामी की कमी के कारण बीज खराब हो रहे रहे है। ऐसे में कई किसान पानी सिंचाई के संसाधन जुटाकर पानी दे रहे है।

### अल्प बारिश से खेतों ने नमी नहीं

ग्राम हमीरगढ़ के किसान अनिल गरवाल ने बताया कि मानसून की सीजन प्रारंभ हुए एक माह होने को आया है। लेकिन अल्प वर्षा के कारण खेती में की गई बुआई में नमी नही होने केवकरण सूखने की कगार पर है। किसानों को

मानसून से काफी उम्मीद थी, परंतु मौसम ने एक बार फिर उन्हें धोखा दे दिया है। जुलाई में भी दिन का तापमान बड़ा हुआ है। जिससे जमीन का तापमान भी अधिक है। अभी तक कम वर्षा के कारण भूमि में नमी नही आई है। खेतो में दरार देखी जा रही है।। अब स्थिति यह है कि किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं।

### मौसम फसलों को बढ़ने ही नहीं दे रहा है

ग्राम सारंगी के किसान सरवन पाटीदार ने बताया कि इस साल मौसम और किसान में बैर सा हो गया है। मानसून को प्रारंभ हुए एक माह हो गया है लेकिन अभी तक ऐसी बारिश नही हुई जिससे किसानो के चेहरे पर खुशी दिखाई दी हो। इस सीजन के लिए इस बार सही समय पर वर्षा नहीं होने से बोवनी कार्य में देरी हुई है। कुछ क्षेत्र में बरसात अच्छी हुई। जहा पर बुआई हो गई लेकिन बुआई के बाद एक पानी की जरूरत होती है वो नही हुई जिससे किसान चिंतित है। बुआई करने के बाद से बारिश के लिए किसान आसमान की ओर देख रहा थे। पिछले करीब चार दिन से तेज धूप निकल रही है। जिससे नमी खत्म हो रही है। जिससे बीज खराब हो सकता है। जिनको बचने के लिए खेतो स्प्रिंकलर फ्वारा पद्धति से खेतो में नमी बनाने के लिए कृत्रिम बरसात कर रहे है। क्षेत्र का किसान बारिश के लिए आसमान की ओर देख रहा है।

दिन भर मौसम बनता है, पर बादल बरसते नही

पिछले एक हप्ते से दिन में उमस वाली गर्मी हो रही है। रोजाना सुबह शाम बादल तो छाए रहते हैं, लेकिन यह सिर्फ बारिश की आस दिखाकर चले जाते हैं। किसान बारिश के इंतजार में हैं, जबकि खेतों में बोवनी कर चुके किसान बरसात के बिना सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्हें बचाने की लिए क्षेत्र के किसान अच्छी बारिश की आस लगाए बैठे है।

# समस्याओं के संकट से घिरी सरकार समाधान के उपायों से दूर

**माही की गूंज, झाबुआ।**

डॉक्टर्स की कमी से जुझता प्रदेश, कुपोषण के कलंक को सर पर लिए, प्यासी सूखी नदियों में भूजल स्तर के गहरे संकट में समाता हुआ जनता के साथ ठगी कर सड़क सुरक्षा के दावों को पिछाड़ता हुआ, दुर्घटनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए लगातार दुर्घटना में मौतों की संख्या में वृद्धी पाकर लोगों के जीवन को दुखमय बनाते हुए, सिंचाई की समस्या से ग्रसित परिवार पालन के लिए पलायन पर जाती जनता के पैरे के छाले नहीं देख पाता। नकली दवा, फर्जी डॉक्टर, एमडी ड्रग्स, नकली खाद्य सामग्री, लव जिहाद, मतांतरण, बालिकाओं के बलात्कार, महिलाओं की असुरक्षा, शिक्षा के नीजीकरण में संचालको की मनमानी, रोजगार की कमी और बच्चों को उचित स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं से प्रदेश जुझ रहा है। वही प्रदेश सरकार झुठे दावे के साथ विकास के वादों के आश्वासन से नागरिको को बहला रही है।

प्रदेश में जन समस्या दिन पर दिन उभरती जा रही है, लगभग हर क्षेत्र में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में समस्याओं के संकट में नंबर एक या दो पर बना हुआ है, और सरकार वादों से जनता को आश्वासन देकर समस्या से मुख मोड़ लेती है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुपोषण की अधिकता बताई साथ ही जनजातिय क्षेत्र में कुपोषण के प्रभाव को अधिक दर्शाया। ऐसी ही एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूजल संकट को भयावह बताकर केंद्रीय भूजल बोर्ड ने मालवा-निमाड़ में भूजल, पेयजल, के संकट को गंभीर बताया। इसी जल संकट के कारण प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों में होने वाले पलायन से गांव खाली हो रहे हैं, लोग अपने घरो को छोड़ अन्य राज्यों में परिवार के पालन के लिए पलायन कर रहे हैं जिससे जनजाति समाज में स्वास्थ्य के गंभीर परिणाम आ रहे हैं, और उनके बच्चें शिक्षा से वंचित होकर अधिक मात्रा में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टी से देखे तो प्रदेश में चिकित्सको की कमी भी है, और दुर्घटनाओं की दृष्टी से भी प्रदेश अव्वल है।

विशेषज्ञों के अनुसार भूजल का दोहन के कारण पेयजल और कृषि दोनों के लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि भूजल पुनर्भरण में 0.47 प्रतिशत की वृद्धी हुई है, इसके विपरित भूजल निकासी में 2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धी दर्ज की गई है। उसी के अनुरुप राज्य का भूजल दोहन स्तर 58.40 प्रतिशत से बढ़ते हुए 59.32 प्रतिशत हो गया है। इसी कारण उम्मिदों के बादल न तो गरज रहे हैं न ही बरस रहे हैं। मध्यप्रदेश जिसे नदियों का मायका कहा जाता है उस प्रदेश में नदिया सूख गई है। छोटी नदियों में पानी नहीं होने पर भूजल स्तर में जो कमी आई है उससे कुछ ही वर्षों में प्रदेश पर गंभीर संकट आ सकता है।

पलायन के पथ पर अग्रसर परिवार पेट पालने की परिक्रमा में भावी पीढ़ी के भविष्य को पथभ्रष्ट कर देते हैं। शिक्षा से वंचित बच्चें जागरुकता के अलख से दूर अस्वस्थ और कमजोर होते हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में सड़को की बदहाली और सड़क सुरक्षा व्यवस्था की बदइंतजामी खुलकर सामने आई है। हादसों में पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश है, 60 प्रतिशत दुर्घटनाएं जिनमें मौके पर ही मौत, 20 प्रतिशत मौतें अस्पताल पहुंचे-पहुंचे ही हो जाती है, वहीं 20 प्रतिशत मौतें उपचार के दौरान हो जाती है। रिपोर्ट में तेज गति के कारण होने वाली दुर्घटना में मध्यप्रदेश अव्वल नंबर पर है। वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण सबसे ज्यादा दुर्घटना मध्यप्रदेश में हो रही है। मध्यप्रदेश में 108 एंबुलेंस सेवा कंपनी की रिपोर्ट जिसमें वर्ष 2025 के आंकड़े निकाले गए है जो कि जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक के है। जिसमें यह बताया गया है कि, प्रदेशभर में जो सवा लाख दुर्घटनाएं हुई है उसमें सबसे ज्यादा शिकार युवा वर्ग हुआ है। इंदौर महानगर में ही बीते पांच वर्षों में दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में वृद्धी पाई गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठीत सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त की है, और कहा है जब दुर्घटनाओं में बड़ोत्तरी और हादसो में मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है तो सड़क सुरक्षा के दावे सही कैसे हो सकते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर और भयावह है, क्योंकि जो प्रदेश का भविष्य बनेगे यह रिपोर्ट उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुपोषण घटने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग सुस्त मंत्री और सुस्त तंत्र की कार्य के प्रति कमजोरी और निष्क्रियता के कारण प्रदेश में कुपोषण इस स्तर पर जा पहुंचा है। वर्ष 2023-2024 में भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि, सम्पूर्ण देश में कुपोषण का सबसे अधिक प्रतिशत मध्यप्रदेश के बच्चों में पाया गया है, और वर्तमान में तो यह प्रतिशत बढ़ा ही है। साथ ही जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण का प्रभाव पहले से और अधिक बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार तो प्रदेश में कुपोषण बढ़ा है परंतु बीते वर्ष ही प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री और कलेक्टर मीणा ने झाबुआ जिले के नाम से मोटी आई को लेकर वाहवाही लूटी थी। यदि मोटी आई योजना प्रभावित थी तो क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट या उसके जांच अधिकारी गलत है। यह प्रश्न कुपोषण पर बढ़ते आंकड़ो पर लोगों को, विभाग को, सरकार को यहां तक कि सर्वेक्षण करने वालों को भी झकझोड़ने वाला है।

रिकेश बैरागी

प्रदेश में जल संकट के साथ भूजल संकट भी तेजी से बढ़ रहा है और प्रदेश सरकार के मुखिया अपने मिया मिट्ठु हो कर अपने ही शागिर्दों से अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। जब रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूजल स्तर गहराता जा रहा है। तब प्रदेश मुखिया दावा कर रहे हैं कि, 19 मार्च से अब तक पूरे 100 दिनों में 3 लाख 63 हजार जल संवर्धन का कार्य किए जा चुके है जिस पर सरकार का 10,514 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है।

बहरहाल, प्रदेश सरकार को झुठे वादें, और दावों से मुक्त होकर धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है साथ ही मुफ्त सुविधा से निर्धन को और निर्धन बनाने से बचना चाहिए। वहीं प्रदेश की समस्याओं को चिन्हित कर उस पर उचित समाधान देकर उन समस्या को समाप्त करना चाहिए।

## संपादकीय

# बुजुर्गों की सुविधा-सुरक्षा अनुकूल हों डिजिटल सेवाएं

तकनीक ने मानव जीवन की रफ्तार को अभूतपूर्व गति दी है। सुबह की चाय के डिजिटल भुगतान से लेकर हवाई टिकट और बैंकिंग तक, सब कुछ अब एक छोटी-सी स्क्रीन पर सिमट गया है। युवाओं के लिए यह सुविधा और अवसर का नया संसार है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए यही दुनिया कई बार उलझन, असुरक्षा और निर्भरता का कारण बन जाती है। अपनों से जुड़े रहने की खुशी और हर काम के डिजिटल होने की मजबूरी के बीच पुरानी पीढ़ी जिस संघर्ष से गुजर रही है, वह आज की एक बड़ी विडंबना बन गई है।

स्मार्टफोन अब केवल युवाओं का उपकरण नहीं रहा। दादा-दादी वीडियो कॉल पर दूर बैठे अपने पोते-पोतियों को देखकर भावुक हो उठते हैं। व्हाट्सएप पर परिवार से जुड़े रहना, पुराने मित्रों को खोजना और यूट्यूब पर भजन सुनना उनके अकेलेपन को काफी हद तक कम करता है। लेकिन यही तकनीक कई बार उनके लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। स्क्रीन पर दर्जनों एप, लगातार आने वाले संदेश, अचानक बदली हुई सेटिंग या किसी जरूरी फाइल के मिट जाने का डर उन्हें हमेशा असहज बनाए रखता है। छोटी-सी तकनीकी चूक भी उनका आत्मविश्वास डगमगा देती है। कई बुजुर्ग इस डर से स्मार्टफोन का सीमित उपयोग करते हैं और हर नए डिजिटल काम के लिए परिवार के किसी सदस्य का इंतजार करते हैं। उनकी आत्मनिर्भरता भी प्रभावित होती है।

सबसे गंभीर चिंता साइबर ठगी का बढ़ता खतरा है। डिजिटल दुनिया की सीमित समझ का फायदा उठाकर अपराधी बुजुर्गों को सबसे आसान निशाना बना रहे हैं। फर्जी बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी बनकर फोन करना अब आम बात हो गई है। डिजिटल अरेस्ट्श् जैसे नए साइबर अपराधों में ठग वीडियो कॉल के जरिए कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर वरिष्ठ नागरिकों से लाखों-करोड़ों रुपये ठग लेते हैं। केवाईसी अपडेट, पेंशन बंद होने या बैंक खाते के सत्यापन के नाम पर ओटीपी और बैंक विवरण हासिल कर जीवनभर की जमा-पूंजी साफ कर दी जाती है। आर्थिक नुकसान उन्हें गहरा मानसिक आघात भी पहुंचाता है, जिससे कई बुजुर्ग अवसाद और असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में ठगी के बाद वे खुद को दोषी मानने लगते हैं, परिवार के सामने अपनी बात रखने से हिचकिचाते हैं। स्थिति आर्थिक ही नहीं, भावनात्मक संकट भी पैदा करती है।

मगर वे इस डिजिटल व्यवस्था से दूर नहीं रह सकते। पेंशन, बैंकिंग, बिजली-पानी के बिल, सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार ऑनलाइन होती जा रही हैं। पहले पेंशनभोगी बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करते थे। अब डिजिटल जीवन प्रमाण की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ उंगलियों के निशान धुंधले पड़ जाने से कई बार सत्यापन सफल नहीं हो पाता। ऐसे में उन्हें बार-बार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंकिंग भी अब पासबुक से आगे बढ़कर पासवर्ड, ओटीपी और मोबाइल एप पर निर्भर हो गई है। एक पासवर्ड भूल जाने का मतलब कई बार अपने ही पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना है। रेलवे टिकट, अस्पताल में पंजीकरण, गैस बुकिंग, बीमा, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जैसी अनेक सेवाओं में भी डिजिटल माध्यम प्रमुख हो चुका है। ऐसे में तकनीक से दूरी का अब विकल्प नहीं रह गया है।

डिजिटल बदलाव का एक सामाजिक पहलू भी है। संयुक्त परिवारों के टूटने और युवाओं के रोजगार हेतु बाहर जाने से बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। ऐसे में मोबाइल और इंटरनेट अनिवार्य जरूरत बन गए हैं। जब उनके सामने तकनीकी समस्या आती है, तब अकेलापन व असहायता का एहसास गहरा हो जाता है। जरूरी है कि डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में भी देखें।

निस्संदेह, तकनीक दौर में चुनौती यह है कि विकास समावेशी हो। डिजिटल सेवाओं का डिजाइन वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। बैंकिंग व सरकारी एप अधिक सरल हों, बड़े वित्तीय लेनदेन में अतिरिक्त मानवीय सत्यापन की व्यवस्था हो तथा साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं। बैंक, डाकघर, पंचायतें, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण शिविर लगाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ने संग, वे तकनीक का सुरक्षित उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल साक्षरता गांव व मोहल्ले तक पहुंचे।

जिन माता-पिता और दादा-दादी ने कभी हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उन्हें डिजिटल दुनिया में हमारा सहारा चाहिए। उनकी हर शंका पर झल्लाने के बजाय धैर्य से समझाना होगा कि कोई बैंक या पुलिस अधिकारी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता और न ही वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी होती है। तकनीक की सफलता तभी है, जब वह हर पीढ़ी को साथ लेकर चले। आधुनिकता का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब हमारे बुजुर्ग भी डिजिटल दुनिया में सम्मान, आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ जी सकें।

# पंजाब की खिसकती सियासी जमीन के मायने

पंजाब की राजनीति में पिछला हफ्ता कुछ ज्यादा ही गर्म रहा। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हाल ही में राज्य के दौरे पर थे य उन्होंने अमृतसर, लुधियाना व जालंधर का दौरा किया ताकि 2027 के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनौतियों की थाह ले सकें। जैसे ही नबीन पंजाब से लौटे, एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला कृत्य करते दिख रहे हैं, जिसने हर ओर हलचल मचा दी।

अकाल तख्त, जिसे व्यापक तौर पर आस्था के मामलों में सिखों द्वारा सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, ने इस वीडियो को लेकर मान को दोषी ठहराया हैय विपक्षी दलों ने भी ऐसा ही किया। मान ने अपने बचाव में भाजपा-शासित गुड़गांव की एक लैब से मिली 'क्लीन चिट' का हवाला दिया-परंतु, जल्द ही हरियाणा पुलिस ने क्लीन चिट की एवज में पैसे के लेन-देन के आरोप में उस लैब के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या मान इस संकट से उबर पाएंगे? क्या इससे 'आप' को बड़ा नुकसान होगा, वह पार्टी जिसने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी या क्या पार्टी पिछले हफ्ते के झटके से उबरकर संकट को अवसर में बदल पाएगी? पिछले हफ्ते तक, ऐसा लग रहा था कि 'आप' आसानी से आगे बढ़ रही है और विपक्ष बिखरा पड़ा है, कोई दल गंभीर चुनौती पेश करने की स्थिति में नहीं। मुख्यमंत्री मान के बीच-बीच में शाम ढले होने वाले चुनावी दौरे शायद ही सतलुज नदी में तरंगें उठा पाए हैं (जिसमें अभी उफान नहीं आया था)। साथ ही, अरविंद केजरीवाल के मुफ्त सुविधाओं के चतुर वादों के साथ-जो लगता है भाजपा की सफल रही रणनीति की नकल है-जिसमें महिलाओं को पैसे देना (अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रु. प्रतिमाह तो अन्य को 1,000 रु.) और सफाई कर्मचारियों, स्कूल शिक्षकों व सरपंचों जैसे महत्वपूर्ण समूहों की शिकायतें दूर करने का वादा शामिल है, 'आप' एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रही है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। पंजाब सांसें थामे इंतजार कर रहा है और सवाल है कि क्या वीडियो से छिड़ी राजनीतिक लड़ाई इस सप्ताह भी जारी रहेगी।

पिछले हफ्ते तक, भाजपा को दौड़ में सिर्फ एक प्रतिभागी भर माना जा रहा थाय लेकिन मची उथल-पुथल के बीच, वह महसूस कर रही कि शायद सियासी जमीन पर पांव जम सकता है। महत्वाकांक्षा को सदैव लोगों को

साथ जोड़ने वाली चीज माना जाता है, लेकिन सवाल है कि क्या यह काफी है? चुनाव में करीब छह माह बचे हैं, क्या भाजपा के पास विधानसभा की सभी सीटों पर लड़ने योग्य 117 उम्मीदवार हैं?

गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नबीन जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं का तो मानना ??है कि हो जाएंगे। श्द ट्रिब्यूनश् की जमीनी रिपोर्ट कहती है कि अकेले अपने दम पर न तो शिरोमणि अकाली दल और न ही भाजपा की स्थिति मजबूत हैय हां, गठबंधन होने पर, मुकाबला करने लायक हो सकते हैं। मेरी सहयोगी अदिति टंडन ने हाल ही में एक वरिष्ठ भाजपा नेता का हवाला दिया है, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि 'राजनीति में कुछ भी संभव है'। इसीलिए गत सप्ताह, जब पंजाब में सियासी परिदृश्य बदल रहा है, सवाल हैरू क्या भाजपा व शिरोमणि अकाली दल, जिनमें 2020 में मोदी सरकार के कृषि कानूनों को लेकर कटु अलगाव हुआ था, आखिर क्या फिर साथ आएंगे?

निश्चित तौर पर, 'राजनीति में एक हफ्ता बहुत लंबा समय होता है', यह एक ऐसी आम बात है जिसे हर राजनेता मानता है-सिवाय राहुल गांधी के, जिनके पास शायद अन्य ज्यादा जरूरी काम हैं, जबकि बीते हफ्ते ही दिल्ली में पंजाब के नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर अहम बातचीत बमुश्किल पूरी हो पाई। याद रहे ,हाल ही में शहरी निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जिससे पता चलता है कि भले ही राज्य में पार्टी बंटी है- मुख्यमंत्री पद के कम से कम पांच दावेदार हैं-फिर भी कांग्रेस की विचारधारा के प्रति लोगों में थोड़ी-बहुत वफादारी अभी भी बची है।

अकाली दल के लिए बड़ी चुनौती है- क्या पंजाब के लोग उसे 'बेअदबी' के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने के लिए माफ कर पाएंगे? यह घटना 2015 में बरगाड़ी कस्बे में हुई थी, जब पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फटे मिले थे-तब अकाली सरकार थी।

निश्चित ही, पिछले हफ्ते विपक्ष भगवंत मान पर कथित वीडियो में वैसी ही गलती करने का आरोप लगा रहा है- जिसे मान और 'आप' जोरदार ढंग से नकार रहे हैं। इसीलिए आगामी दिन चुनाव प्रचार की चाल-ढाल तय करेंगे। क्या मुख्यमंत्री इस मुश्किल दौर से पार पा सकेंगे और अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? या क्या पंजाब 2027 में 'आप' के साथ वही करेगा जो उसने 2017 में अकाली दल के साथ किया था?

2027 की लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है। अकाल तख्त ने पहले ही आदेश दे दिया है कि पंजाब भर के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में मान की निंदा वाले बैनर लगाए जाएं। कई जगह इस पर अमल हो भी गयाय लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ स्वतंत्र प्रबंधन व सिंह सभा से जुड़े गुरुद्वारों में अभी ऐसा नहीं किया। स्थिति अभी भी साफ नहीं है।

एक और तथाकथित पार्टी है, श्वारिस पंजाब देश्, जिसके सांसद अमृतपाल सिंह खडूर साहिब सीट से तब चुने गए थे जब वे असम की जेल में थे व अभी वहीं हैं। पंजाब में हालात बदल रहे, नए माहौल में इस दल की स्थिति क्या होगी?

बीते हफ्ते जब हालात धुंधला रहे थे और लोग सोच रहे थे कि आगे क्या होगाय राज्य का परिदृश्य है कि सूबा एक ऐसी धुरी पर घूम रहा है जिसे उसने खुद नहीं बनाया। अमृतसर में श् द ट्रिब्यूनश् के पत्रकार पवन के. जायसवार का कहना है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर रोजाना हेरोइन और छोटे हथियारों की बरामदगी बढ़ रही हैय पुलिस अफसरों का कहना है कि सीमा पार से आने वाले ड्रोन अत्याधुनिक हो रहे, जो

ज्योति मल्होत्रा

कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बच सकते हैं और नशा एवं हथियारों की बड़ी खेप लाने में सक्षम हैं।

जालंधर से अपर्णा बनर्जी की द्वारा की गईं खबरें जिनमें हेरोइन की वजह से पूरे के पूरे परिवार खत्म होना नशे की राक्षसी जकड़ दर्शाती है। आप का अभियान श्युद्ध नशेयां विरुद्धश् स्वागत योग्य है क्योंकि यह संकट को काफी हद तक उजागर करता है, लेकिन चुनौती इतनी बड़ी है कि पुनर्वास का काम सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं किया जा सकता। पंजाब को बचाना है, तो एक व्यापक कार्ययोजना के लिए सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष, दोनों को, साथ आना होगा। कभी-कभी स्थिति तब बदतर हो जाती है-जब नशा तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी भी मिल जाए। पिछले हफ्ते भाजपा ने अमृतसर से अपने एक स्थानीय वरिष्ठ नेता को बर्खास्त कर दिया, जब उसके बेटे के पास से-जो कथित तौर पर नशे का आदी है-बीएसएफ ने एके-47 समेत 26 आधुनिक हथियार बरामद किए।

शायद गत सप्ताह का आखिरी जिक्र मेरे साथियों नेहा सैनी और राजमीत सिंह की खबरों से होना चाहिए। उन्होंने गौर किया है कि राजनीतिक पार्टियों को वर्तमान में फायदा उठाने के लिए इतिहास का आह्वान करना पसंद है-चाहे यह 2022 के चुनाव में आप का शहीद भगत सिंह के नाम का उपयोग करना हो या आज भाजपा द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के श्सरकार-ए-खालसाश् का जिक्र करना (ऐसा सिख राज्य जो धर्मनिरपेक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला था)।

तो जैसा कि पंजाब में होता है, अतीत और वर्तमान आपस में घुले-मिले हैं, वैसे ही जैसी एक-दूजे में समा जाने वाली यहां की नदियां। सवाल है कि क्या ये नदियां समुद्र की राह खोज पाएंगी और कैसे।

# भरोसे के संकट को दूर करने की जरूरत

सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में ज्ञानार्जन की समस्या है, पुस्तक संस्कृति के घटते जाने की समस्या है। हमने 2024 में नीट की परीक्षा आयोजित की। नकल और अवैध तरीकों के इस्तेमाल के कारण परीक्षा की शुद्ध?ता बुरी तरह से प्रभावित हुई और लाखों छात्रों को पुनरू परीक्षा देनी पड़ी। यदि इस अनुभव से सबक लेते तो इस बार दोबारा परीक्षाएं आयोजित न करनी पड़ती। लेकिन 2026 में जब फिर नीट परीक्षा आयोजित हुई तो फिर पेपर लीक का मामला उजागर हुआ। इस घटनाक्रम ने देश की पठन-पाठन, शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन की शुचिता के बारे में बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। भारत के युवाओं का भविष्य सटीक ज्ञान के बगैर अधूरा है और चोर गलियों से सफलता के प्रतिमान स्थापित नहीं किए जा सकते।

देश में नीट की परीक्षा दूसरी बार जिस तरह आयोजित हुई, जिनकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई। प्रश्न पत्रों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल, टेलीग्राम एप को बंद कर देने जैसे उपाय छात्रों को त्रिस्तरीय जांच के बाद ही परीक्षा केन्द्रों में भेजा गया। बायोमीट्रिक जांच हुई, फिजिकल जांच हुई, दूसरे दस्तावेज जांचे गए। सात लाख सुरक्षा कर्मी और पर्यवेक्षक तैनात रहे। हर परीक्षा कक्ष में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया।

करीब 1.38 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों से 95 हजार कक्षों पर नजर रखी गई और छात्र जाम में न फंसें, इसलिए प्रधानमंत्री भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 45 मिनट रुके रहे। इसके बावजूद बिहार में 9 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए । जिनमें 7 मेडिकल के छात्र थे। सबसे पहले जब पहली बार परीक्षा हुई तो 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, इस बार दोबारा परीक्षा हुई तो 20 लाख छात्र परीक्षा देने बैठे। पहला सवाल यही है कि दो लाख से अधिक छात्र दोबारा क्यों नहीं

बैठे? चाहे रिपोर्ट कहती है कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और कहीं गड़बड़ी की सूचना नहीं है। लेकिन गड़बड़ी तो पहले ही पैदा हो गई थी जब पहली परीक्षा के बाद दोबारा परीक्षा की घोषणा से पूरे देश में अवसादग्रस्त होकर कई युवा छात्रों ने आत्महत्या कर ली।

केन्द्र सरकार के दर्जनों मंत्रालयों के साथ राज्य सरकारों व एजेंसियों ने 37 दिनों तक एकजुट होकर काम किया। यह सही है कि परीक्षाएं पूरी तरह से सफल रहने की घोषणाएं की जा रही हैं लेकिन असल में ये कितनी सफल हुई हैं इसका पता तो परिणामों की घोषणा के साथ ही चलेगा। शिक्षाविदों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अचानक इतने वर्षों के बाद परीक्षा व्यवस्था इतनी भयावह समस्या क्यों बन गई कि इसके आयोजन के लिए वायुसेना से लेकर लाखों पुलिसकर्मियों की मदद लेनी पड़ीय और इसके बावजूद बड़े पैमाने पर नकल करते हुए छात्र पकड़े जा रहे हैं। क्या इस स्थिति का मूल कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रति पैदा हुआ अविश्वास है?

आज कुछ संस्थाएं परीक्षा की ठेकेदारी कर रही थीं, उन्हीं पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पेपर लीक किए हैं। क्यों विद्यार्थियों पर इतना अविश्वास किया गया कि उनके परीक्षा केन्द्र बदलकर उन्हें दूर-दूर तक परीक्षा देने जाना पड़ा। जैसे पहले के वर्षों में चलता रहा है क्या उसी तरह से परीक्षाएं उन्हीं केन्द्रों में नहीं करवाई जा सकती थीं, जहां से छात्र संबंध रखते थे।

अगर थोड़ा-सा विश्वास वरिष्ठ शिक्षक जनों पर करके परीक्षा प्रणाली को उनके हवाले कर दिया जाता तो शिक्षक अपने पेशे के प्रति ईमानदार होते हुए अपनी अंतरात्मा का हनन कभी नहीं करेंगे अभी भी 90 प्रतिशत शिक्षक ऐसे ही हैं। उन मासूम छात्रों के बारे में सोचा जाए जिन्होंने दिन-रात एक करके पूरी मेहनत से परीक्षाएं दीं लेकिन अचानक उन्हें यह संदेश दिया गया कि पिछली मेहनत व्यर्थ है, अब दोबारा परीक्षा दो। हम समझते हैं कि इस समस्या का समाधान यही है कि परीक्षा लेने वालों और परीक्षा देने वालों पर पूरा विश्वास किया जाए। उनके लिए सुविधाजनक केंद्र बनाए जाएं। तब

सुरेश सेठ

असामाजिक तत्व सारा तंत्र बिगड़ने पर आमादा हो जाएं तो उन्हें चुनकर बाहर फेंकना आसान हो जाएगा।

इस समय परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। यह नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, पूरी मेहनत और शिक्षण और शिक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण के बिना नहीं हो सकता। अपराधी तलाश करने की जगह छात्रों की मेहनत और अध्यापकों के नैतिक कर्तव्य पर विश्वास को प्राथमिकता दी जाए तो परीक्षाओं की ईमानदारी से करवाने की इस जटिल गुत्थी को सुलझाने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। आने वाला भारत डिजिटल होने जा रहा है। यहां शिक्षा के अलग-अलग आयामों में आमूलचूल परिवर्तन होगा। एआई तकनीकें सामने आ रही हैं। साइबर शक्ति बढ़ रही है। इन्हें सीखने का क्रम चलता रहे और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो हर वर्ष ऐसे एक देश एक परीक्षा जैसे आयोजन निरापद ढंग से पूरे हो सकेंगे।

# राजनीति का बदरंग चेहरा दिखाता दल-बदल

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना फिर टूट गई है। पहले चालीस विधायकों ने बगावत की थी और अब उद्धव के छह सांसद पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं। एक को छोड़कर बाकी पांच ने यह कदम उठाने का कारण बताते हुए मूल शिवसेना की नीति-रीति का हवाला दिया है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए कांग्रेस का साथ दिया है, जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उनसे पूछा जाना चाहिए जब शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने उद्धव का दामन छोड़ा था, तब भी तो यही स्थिति थी। तब उन्होंने शिंदे का साथ क्यों नहीं दिया? अब भाजपा में जाने वाले इन सांसदों ने अपने इस कदम उठाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया। हां, उद्धव ठाकरे के साथ खड़े बचे-खुचे 'शिवसैनिकों' ने यह आरोप अवश्य लगाया है कि भाजपा ने उन्हें 15 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपये तक की 'रिश्वत' देकर शिवसेना को तोड़ा है।

यह पहली बार नहीं है जब दल-बदलू राजनीति का बदरंग चेहरा सामने आया है। देश में 'आयारामों -गयारामों' की एक लंबी सूची है। दल-बदलुओं की यह कथा लगभग छह दशक पहले शुरू हुई थी। कहानी अब भी जारी है। तब भी दल-बदल के पीछे कारण कोई सिद्धांत या नीति नहीं थी और अब भी दिखाई यही दे रहा है कि राजनीतिक और आर्थिक लाभ ही इस जनतंत्र-विरोधी कार्रवाई का मूल कारण है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने शायद ही कभी सोचा होगा कि हमारे राजनेता इस स्तर तक जायेंगे, पर आज यह स्थिति एक खुली किताब की तरह सामने है। न दल बदलने वालों को शर्म आती है और न दल बदल करवाने वालों को।

हां, पिछले लगभग एक दशक से देश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ हैद्द मूल्यों- सिद्धांतों को ताक में रखकर किसी भी कीमत पर राजनीतिक लाभ उठाने वाला अध्याय। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया था-कांग्रेस मुक्त भारत अभियान। सत्ता में आने के साथ ही भाजपा ने अपने इस सपने को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी थी। और उसे कुछ सफलता भी मिलने लगी थी। पार्टी का हौसला बढ़ गया। इस हौसले के सामने सही-गलत कोई माने नहीं रखता था। वैसे भी राजनीति में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती, पर राजनीति के इस नये दौर में सब कुछ जायज था। इस रीति-नीति के परिणामस्वरूप 'वाशिंग मशीन' वाली राजनीति ने रंग दिखाना शुरू किया। राजनेताओं पर आरोप लगने या अपराध स्पष्ट हो जाने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। जो हमारे साथ है वह सही है वाली यह राजनीति किसी भी कीमत पर अपने उद्देश्य को पूरा करने में विश्वास करती है। सत्ता पाना और सत्ता पर बने रहना ही जैसे राजनीति का एकमात्र उद्देश्य हो! खतरनाक है यह स्थिति और सबसे बड़ा खतरा जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर है।

देश की राजनीति का जो अध्याय आज लिखा जा रहा है, वह सिर्फ सत्ता हथियाने की या सत्ता में बने रहने के प्रयासों की कहानी ही नहीं है, खतरे में हमारा लोकतंत्र है। यह अध्याय 'कांग्रेस मुक्त भारत' के नारे से शुरू हुआ था, अब वह 'विपक्ष मुक्त भारत' की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह आज छोटे और क्षेत्रीय दलों को तोड़ा जा रहा है, वह जनतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अंग्रेजी में एक कहावत है 'लाउड एंड क्लियर' यानी पूरी तरह स्पष्ट। इसे अनदेखा या अनसुना करना जनतंत्र के प्रति अपने दायित्व से मुंह चुराना ही है।

मजबूत विपक्ष जनतंत्र के औचित्य और सफलता की एक महत्वपूर्ण शर्त है। मजबूत सरकार की तरह ही एक सुदृढ़ विपक्ष भी चाहिए होता है। कमजोर विपक्ष का मतलब होता है एक ऐसी सरकार को अवसर और छूट देना जो कभी भी तानाशाही का रास्ता अपना सकती है। आप चाहें तो इसे निर्वाचित तानाशाही कह सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए जागरूक मतदाता की आवश्यकता है जो जनतंत्र की सफलता में मजबूत विपक्ष की महत्ता और आवश्यकता को समझे और ऐसी किसी भी कार्रवाई के प्रति सजग रहे जो जनतंत्र को कमजोर बनाती है।

आज जिस तरह छोटे राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें अप्रासंगिक बनाने का प्रयास हो रहा है, उससे हमारा जनतंत्र कमजोर ही होगा। हाल ही के दिनों में हुई दल-बदल की घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि अजनतांत्रिक ताकतें लगातार सक्रिय हो रही हैं। कुछ अर्सा पहले हमने पंजाब के आम आदमी पार्टी के सांसदों को दल-बदल करके भाजपा की शरण में जाते देखा था। फिर हमने देखा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की पराजय के बाद उसके विधायकों और सांसदों ने दल-बदल करना जरूरी समझ लिया। नवीनतम उदाहरण महाराष्ट्र में टूटी हुई उद्धव ठाकरे की पार्टी को और तोड़ने का है। जैसी स्थितियां बन रही हैं, उनसे इस आशय के संकेत भी मिल रहे हैं कि टूटने-बिखरने का खतरा शरद पवार की एनसीपी को भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री इस आशय के संकेत दे रहे हैं कि अखिलेश यादव की सोशलिस्ट पार्टी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ताकत भी घटा दी गयी है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।

यह सब घटनाएं बताती हैं कि किस तरह देश में विपक्ष को कमजोर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। विपक्ष के कमजोर होने का मतलब जनतंत्र का कमजोर होना है और जनतंत्र कमजोर होता है तो तानाशाही प्रवृत्तियों को सिर उठाने का अवसर मिल जाता है।

देश में केंद्र में मजबूत सरकार हो, यह एक अच्छी स्थिति है। इसी तरह राज्यों में सरकारें ताकतवर हों, इसमें भी कहीं कुछ गलत नहीं है। पर यह मजबूती और ताकत जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में मजबूत सरकार का भी दायित्व बनता है कि वह जनतांत्रिक परंपराओं को, जनतांत्रिक मूल्यों को पनपाने के प्रति भी सावधान रहे।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो संसद में विपक्ष की स्थिति बहुत कमजोर थी। कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें प्राप्त हुई थीं। विपक्ष को मिली कुल 125 सीटों में सबसे बड़ा दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसे मात्र 16 सीटें मिली थीं। भारतीय जन संघ के हिस्से में सिर्फ तीन सीटें आयी थीं। तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा था, चूंकि विपक्ष सदन में कमजोर है, इसलिए उन्हें ही विपक्ष की भूमिका भी निभानी होगी। अर्थात? सरकार के काम-काज पर नजर रखनी होगी। पहले प्रधानमंत्री का यह कथन जनतांत्रिक मूल्यों में तो उनके विश्वास और आस्था को दर्शाता ही है, यह भी बताता है कि वे जनतंत्र की सफलता के लिए ताकतवर विपक्ष की उपस्थिति को कितना जरूरी समझते थे।



विश्वनाथ सचदेव

लेकिन आज स्थिति बदल गयी है। सत्तारूढ़ पक्ष येन-केन प्रकारेण विपक्ष को कमजोर बनाना चाहता है। दल-बदल को बढ़ावा देने वाले 'आपरेशन लोटस' अथवा 'आपरेशन टाइगर' जैसे प्रयास यही बताते हैं। ऐसे प्रयासों को विफल बनाना जरूरी है, ताकि जनतंत्र जिंदा रहे।

दलबदल से बचने के लिए जरूरी है कि दल-बदल कानून को मजबूत बनाया जाये। पहली जरूरत तो यह है कि दल-बदल करने वालों को सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने की शर्त हो। निर्वाचित सदस्यों के दल-बदल का मतलब मतदाताओं को धोखा देना ही है। नैतिकता का तकाजा है कि वे दल बदलना चाहते हैं तो पद से त्यागपत्र दें। फिर से चुनाव लड़ें। पता नहीं दल-बदल कानून बनाते समय यह बात क्यों छोड़ दी गयी थी। अब जोड़ा जाना चाहिए इसे। पर यह होगा कैसे? जो यह कर सकते हैं, वे स्वयं दल-बदल को बढ़ावा देने वाले हैं! पर कुछ तो होना ही चाहिएद्द मुद्दा जनतंत्र को जीवित रखने का है!

# रंजिश में बेटे की जगह पिता की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

**माही की गूंज, मंदसौर।**

शहर के अभिनंदन क्षेत्र स्थित जग्गाखेड़ी रोड पर 27 जून को हुए रवि माली हत्याकांड का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें तीन वयस्क और एक विधि-विरुद्ध बालक शामिल है। पुलिस के अनुसार यह हत्या करीब ढाई माह पूर्व हुए अरुण वर्मा हत्याकांड का बदला लेने के उद्देश्य से की गई थी। मामले में कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

पुलिस को 27 जून को डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि अभिनंदन क्षेत्र की कच्ची सड़क पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है। पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कर्मचारी कॉलोनी निवासी रवि माली के रूप में हुई।

मृतक के परिजन सुमित माली की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) एवं 3(5) के तहत यश उर्फ यशवंत माली, आकाश वर्मा, विकास वर्मा, राज वर्मा सहित अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था।

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देशन एवं कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में गठित दल ने जांच शुरू की। मुखबिरों से छह लोगों के शामिल होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मंदसौर के अलावा रतलाम, इंदौर, प्रतापगढ़ और नीमच में लगातार दबिश दी। जांच के दौरान एक विधि-विरुद्ध बालक को इंदौर से पकड़ा गया। इसके बाद मुख्य आरोपी अजय वर्मा, आशीष वर्मा तथा संदीप उर्फ दिलीप उर्फ काला वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि करीब ढाई माह पहले उनके भाई अरुण वर्मा की हत्या युवराज माली और उसके साथियों ने कर दी थी। इसी रंजिश के चलते उन्होंने युवराज माली के पिता रवि माली की हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया।

थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 5 अप्रैल की रात गांधी चौराहे पर अरुण वर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में रवि माली के बेटे कुलदीप माली सहित अन्य आरोपियों के नाम सामने आए थे। इसी घटना का बदला लेने के लिए रवि माली की हत्या की गई।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस अभिरक्षा में लिया है। पूछताछ के दौरान फरार आरोपियों तथा घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में कुछ और लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है।

## रोजगार सहायक की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने जनसुनवाई में की शिकायत

### शिकायतकर्ता में सरपंच और उपसरपंच भी शामिल

**माही की गूंज, पेटलावद।**

पेटलावद विकासखंड की ग्राम पंचायत रामपुरिया के निवासी इन दिनों रोजगार सहायक सुनील भीमसिंह गरवाल की कार्यप्रणाली से बेहद परेशान हैं। पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से जनसुनवाई में पहुंचकर रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक अपनी मनमानी और दादागीरी के बल पर पंचायत को निजी संपत्ति की तरह चला रहा है और खुलेआम शासकीय धन का बंदरबांट कर रहा है। शिकायत में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आरोपी सुनील गरवाल खुद को कानून से ऊपर मानता है और हमेशा यह धौंस जमाता है कि जो वह कहेगा, वही होगा।

भ्रष्टाचार की परतें खोलते हुए ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत अमृत सरोवर तालाब के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। शासकीय दस्तावेजों में जिस अमृत सरोवर का जिक्र कर राशि का आहरण किया गया, वह पंचायत के आखिरी छोर पर स्थित है और निर्माण के नाम पर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक ने वर्ष 2007-08 में बने पुराने तालाब की लोकेशन का उपयोग कर फर्जी मस्टर रोल तैयार किए। इतना ही नहीं, मस्टर रोल में उन लोगों की हाजिरी दर्शाकर पैसे निकाल लिए गए, जो वास्तव में बामनिया में अपनी दुकानों पर कार्यरत थे और मौके पर मौजूद ही नहीं थे।

### आवास योजना में भी गरीब हितग्राहियों को निशाना बनाया

शिकायत के अनुसार, रोजगार सहायक ने हर किस्त जारी करने के एवज में हितग्राहियों से पांच-पांच हजार रुपये की अवैध वसूली की है। एक दिव्यांग हितग्राही से भी पैसे लेने में उसने कोई संकोच नहीं किया। ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों से पैसे लेने के बावजूद रोजगार सहायक ने न तो जियो-टैगिंग कराई और न ही उनकी किस्त की राशि जारी की, जिससे मजबूरी में ग्रामीणों को बाजार से भारी ब्याज पर कर्ज लेकर अपने मकान बनाने पड़े। जिन गरीबों को कहीं से उधार नहीं मिल पाया, उनके मकान आज भी अधूरे पड़े हैं और वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों ने मांग की है कि वर्ष 2023 से 2026 तक मनरेगा के तहत किए गए सभी निर्माण कार्यों की बारीकी से जांच की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच होती है तो रोजगार सहायक का पूरा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। पंचायत के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल प्रभाव से आरोपी रोजगार सहायक सुनील गरवाल को निलंबित करने तथा शासकीय राशि के दुरुपयोग की वसूली करने की अपील की है।

## सीवरेज योजना से खोदी गई सड़कें बनी परेशानी, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

**माही की गूंज, मंदसौर।**

अमृत 2.0 सीवरेज योजना के तहत शहर में खोदी गई सड़कों तथा अधूरे मरम्मत कार्य के विरोध में बुधवार को शहर ब्लॉक कांग्रेस ने गांधीनगर क्षेत्र में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं एवं पार्षदों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सड़कों की शीघ्र मरम्मत तथा जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस का आरोप है कि अमृत 2.0 सीवरेज योजना के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई की गई थी। कार्य पूर्ण होने के बाद भी सड़कों का समतलीकरण और पुनर्निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया गया। इसके कारण कई स्थानों पर गहरे गड्ढे और निर्माण सामग्री का मलबा पड़ा हुआ है, जिससे आमजन का आवागमन प्रभावित हो रहा है।

ज्ञापन में बताया गया कि योजना का कार्य सबसे पहले वार्ड क्रमांक 39 के ऋषियानंद वार्ड अंतर्गत मेघदूत नगर, यश नगर और गांधीनगर तथा वार्ड क्रमांक 26 के पशुपतिनाथ वार्ड अंतर्गत चंद्रपुरा और सीतामऊ फाटक क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर किया गया था। आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद संबंधित एजेंसी ने सड़कों को पूर्व स्थिति में नहीं लौटाया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्षा ऋतु और रात्रिकाल में गहरे गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। दोपहिया वाहन चालकों, बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में 28 जून को गांधीनगर क्षेत्र में गड्ढों के कारण हुए हादसे का भी उल्लेख किया गया, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे और लोग घायल हुए थे।

कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि शहर की सभी खोदी गई सड़कों का तत्काल निरीक्षण कराया जाए तथा तीन से पांच दिनों के भीतर गड्ढों को भरकर गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कराया जाए। साथ ही योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, संबंधित एजेंसी और ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर जवाबदेही तय की जाए।

## सेंट्रल बैंक घोटाला :पूर्व शाखा प्रबंधक को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

**माही की गूंज, रतलाम।**

बड़ावदा स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 44 लाख रुपये से अधिक के गबन के मामले में विशेष न्यायालय ने पूर्व शाखा प्रबंधक नेविल कावराना निवासी मुंबई को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार शाम उसे जेल भेज दिया गया। मामले में छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि दो आरोपियों का पूर्व में निधन हो चुका है। फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजीव कटारे ने सुनाया।

अभियोजन विभाग की प्रभारी उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक आशा शाक्यवार ने बताया कि वर्ष 2012 से 2014 के बीच बड़ावदा शाखा में 44 लाख 46 हजार 717 रुपये के गबन का मामला सामने आया था। मुख्य आरोपी नेविल कावराना के स्थानांतरण के बाद शाखा में पदस्थ नए प्रबंधक सुमित जैन द्वारा की गई जांच में अनियमितताओं का खुलासा हुआ। इसके बाद विस्तृत प्रतिवेदन बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों तथा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन को भेजा गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नेविल कावराना ने शाखा प्रबंधक रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर बैंक की राशि का गबन किया और धनराशि अपने, परिजनों तथा बैंक के व्यवसाय सहयोगी देवेंद्र कुमार सांड एवं उसके परिजनों के खातों में स्थानांतरित कर अवैध लाभ प्राप्त किया।

जांच में सामने आया कि किसानों की जानकारी और सहमति के बिना उनके किसान क्रेडिट कार्ड तथा अन्य खातों से राशि काटी जाती थी। इसके बाद विभिन्न खातों में धनराशि स्थानांतरित कर दी जाती थी। फसल बीमा कंपनियों और शासकीय राजस्व मद के नाम पर मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) तैयार किए जाते थे, लेकिन उन्हें संबंधित संस्थाओं को भेजने के बजाय निरस्त कर राशि को विभिन्न निजी खातों में जमा कर लिया जाता था।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन ने विवेचना के बाद कुल नौ आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने मुख्य आरोपी नेविल कावराना को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सह-आरोपी देवेंद्र कुमार सांड और कांता सांड का पूर्व में निधन हो चुका है। वहीं खुर्शीद कावराना, जिमी कावराना, यास्मीन कावराना, जिजी कावराना, गुलनाज कावराना मेहता, शहजाद मेहता तथा प्रीति सांड के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।

## सुनेरा सहकारी संस्था गबन मामले में दो दोषियों को चार-चार वर्ष की सजा

**माही की गूंज, शाजापुर।** जिले की कृषि साख सहकारी संस्था सुनेरा में खाद एवं बीज गबन मामले में न्यायालय ने बुधवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक नीरज द्विवेदी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2020 का है। संस्था से जुड़े मेहरबानसिंह राजपूत और मांगीलाल शर्मा पर किसानों को वितरण के लिए रखे गए खाद एवं बीज के गबन का आरोप था। जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने 21 लाख 83 हजार 283 रुपये मूल्य की सामग्री का गबन किया था।

अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने आर्थिक अनियमितता को छिपाने के लिए संस्था के अभिलेखों तथा अन्य शासकीय दस्तावेजों में जानबूझकर हेरफेर की थी। मामला उजागर होने के बाद सुनेरा थाना पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता नीरज द्विवेदी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच-पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

## रिश्वत लेते पकड़ा गया हेड कॉन्स्टेबल, न्यायालय ने भेजा जेल

**माही की गूंज, रतलाम।**

औद्योगिक क्षेत्र थाने में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई को रिश्वत लेने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार रात उसे भीलवाड़ा में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। मामले के बाद आरोपी पुलिसकर्मी के निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है।

आरोप है कि हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई ने जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद लियाकत (70) के साथ मारपीट नहीं करने तथा जांच में सहयोग करने के बदले एक लाख 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। बताया गया है कि वह 10 हजार रुपये की पहली किस्त पहले ही ले चुका था। सोमवार को 50 हजार रुपये लेते समय उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार न्यायालय से रिमांड मिलने के बाद सहायक उपनिरीक्षक कैलाश सैनी, हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई तथा एक अन्य पुलिसकर्मी 28 जून को आरोपी लियाकत को लेकर भीलवाड़ा गए थे। वहां पुलिस दल एक होटल में रुका हुआ था। इसी दौरान आरोपी के परिजनों से रिश्वत लेते समय एसीबी ने तपेश गोसाई को पकड़ लिया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस दल धोखाधड़ी के आरोपी को लेकर रतलाम लौट आया।

मामला रतलाम के व्यापारी रतन जांगिड़ की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार भीलवाड़ा निवासी मोहम्मद लियाकत ने रतलाम स्थित बंद पड़ी एक ऑयल मिल और जमीन का 11 करोड़ 10 लाख रुपये में सौदा कराया था। आरोप है कि उसने 25 लाख 76 हजार रुपये प्राप्त कर लिए, लेकिन न तो जमीन का अनुबंध कराया और न ही वास्तविक मालिक से मुलाकात कराई। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

राजस्थान में रिश्वत लेते हुए रतलाम के हेड कॉन्स्टेबल की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से बच रहे हैं।

## सांदीपनि विद्यालय की परिवहन व्यवस्था पर उठे सवाल, विद्यार्थियों को हो रही परेशानी

**माही की गूंज, शाजापुर।**

लालघाटी स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल सांदीपनि विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही परिवहन व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विद्यालय में 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी बस व्यवस्था सुचारु नहीं हो सकी है। विद्यालय के लगभग 2600 से 2800 विद्यार्थियों के परिवहन की जिम्मेदारी केवल 11 बसों पर होने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बुधवार सुबह गांधी हॉल क्षेत्र में कई विद्यार्थी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बस का इंतजार करते रहे। बताया गया कि एक बस पहले 60 विद्यार्थियों को लेकर विद्यालय पहुंची और उसके बाद वहीं खड़ी रही। शेष विद्यार्थियों के लिए तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। बाद में शिकायत मिलने पर बस दोबारा भेजी गई और विद्यार्थियों को विद्यालय पहुंचाया गया।

विद्यालय के अधिकृत समूह में भी यह निर्देश जारी किया गया है कि एक बस में 60 से अधिक विद्यार्थियों को नहीं बैठाया जाए। ऐसे में अतिरिक्त विद्यार्थियों को बस में स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिससे कई विद्यार्थी या तो लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं या फिर विद्यालय नहीं पहुंच पाते।

एक छात्रा के अभिभावक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद छात्रा को बस से उतारे जाने का आरोप भी सामने आया है। आरोप के अनुसार शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया और शिकायत वापस नहीं लेने पर छात्रा को बीच रास्ते उतार दिया गया। छात्रा ने बताया कि बसों में पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को लगातार परेशानी हो रही है।

अभिभावकों ने भी परिवहन व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि कई बार बच्चों को विद्यालय पहुंचाने के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों के 30 से 40 विद्यार्थी प्रतिदिन प्रभावित हो रहे हैं।

बस चालक रईस ने भी बसों की कमी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उपलब्ध बसों में पर्याप्त स्थान नहीं है और यह समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है।

विद्यालय की प्राचार्य सविता सोनी ने कहा कि बसों की कमी के कारण विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। अतिरिक्त बसों की मांग वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी गई है तथा विद्यार्थियों और मार्गों से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर बसों के अतिरिक्त चक्कर भी लगाए गए हैं।

छात्रा को बस से उतारे जाने के आरोप पर प्राचार्य ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही बस समन्वयक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि छात्रा को बीच रास्ते उतारा गया है तो यह गंभीर विषय है। इस संबंध में समन्वयक को नोटिस जारी कर मामले की जानकारी भोपाल स्तर तक भेज दी गई है।

परिवहन व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच अभिभावकों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और नियमित परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की है।

# खादू, श्याम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न, भंडारे में श्रद्धालुओं ने ग्रहण की प्रसादी

**माही की गूंज, बड़वानी।**

जिले के ग्राम तलून स्थित खादू श्याम मंदिर का प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव बुधवार को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ संपन्न हो गया। खादू श्याम जनकल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में 26 जून से प्रारंभ हुए इस धार्मिक आयोजन में बाबा खादू श्याम, महादेव परिवार तथा कार्य सिद्धि बालाजी भगवान की प्रतिमाओं की वैदिक विधि-विधान से प्राण-प्रतिष्ठा की गई।

समापन अवसर पर आयोजित भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रेमसिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी तथा विधायक राजन मंडलोई सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रेमसिंह पटेल, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल एवं जिला अध्यक्ष अजय यादव ने स्वयं श्रद्धालुओं को प्रसादी परोसी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल रूप से संबोधित किया। उन्होंने उपस्थित संतों को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए देवस्थान की प्राण-प्रतिष्ठा के संकल्प की पूर्णाहुति का यह अत्यंत मंगलमय अवसर है। उन्होंने कहा कि भगवान की प्राण-प्रतिष्ठा केवल प्रतिमा स्थापना नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का आवाहन है, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों के केंद्र को उजागर करती है।

मुख्यमंत्री ने बाबा श्याम को हारे का सहारा बताते हुए कहा कि वे अपने भक्तों के दुःख में सदैव संबल बनकर खड़े रहते हैं। उन्होंने बड़वानीवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ पर स्थापित यह मंदिर जिले की पहचान और गौरव को नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में महंत शशिगिरी महाराज के त्याग और तपस्या का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महंत जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग कर धर्म मार्ग को अपनाया तथा लगातार सात वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर कठोर तपस्या की। उन्होंने कोविड काल में महंत जी द्वारा किए गए समाजसेवा कार्यों की भी प्रशंसा की और कहा कि संत समाज में सूर्य के समान प्रकाश फैलाने का कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के दोनों प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर को और अधिक भव्य स्वरूप देने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तलून गांव में निर्मित यह धाम भविष्य में केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि सेवा, परोपकार और मानवता का भी प्रेरणास्रोत बनेगा।

## पलटी ओवरलोड ऑटो रिक्शा, महिला की मौत, सात घायल

**माही की गूंज, बड़वानी।**

अंजड़ रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप के सामने बुधवार दोपहर सवारियों से भरी एक ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 60 वर्षीय संगीता गोले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा में क्षमता से अधिक 10 से ज्यादा सवारियां बैठी थीं।

घायल अनीता बाई ने बताया कि सभी यात्री करंजा चौराहे से ऑटो रिक्शा में सवार होकर ग्राम तलून जा रहे थे, जहां खादू श्याम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव एवं भंडारे का आयोजन था। नायरा पेट्रोल पंप के सामने अचानक एक मोटरसाइकिल आ जाने पर चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया।

सड़क से नीचे उतरने के बाद चालक ऑटो रिक्शा पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन दो बार पलट गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्काल घायलों को बाहर निकाला तथा पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। इस दौरान संगीता गोले ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे में रिंकू शांतिलाल (40), अनीता शिवजी (45), रेखा सुभाष (40), विद्या अरुण (55), जमना जगदीश (60), शिवकन्या राजेश (40) एवं कलाबाई सत्यनारायण (60) घायल हुए हैं। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति स्थिर बनी हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारियां बैठी थीं, जिससे संतुलन बिगड़ने की आशंका बढ़ गई। मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास में वाहन का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका संगीता गोले (60) सतपुड़ा कॉलोनी की निवासी थीं। पुलिस मोटरसाइकिल चालक की तलाश कर रही है तथा मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

## उफनते नाले में यात्रियों से भरी बस उतारी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

**माही की गूंज, खरगोन।**

भगवानपुरा के आदिवासी क्षेत्र में बाढ़ के दौरान एक निजी यात्री बस को तेज बहाव वाली पुलिया से निकालने का मामला सामने आया है। तेज बारिश के बाद पहाड़ी नदी में आए उफान के बावजूद चालक ने यात्रियों से भरी बस को पुलिया से पार करा दिया। घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया।

जानकारी के अनुसार यह घटना 28 जून की है। उस दिन पहाड़ी क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के बाद नदी-नालों में बाढ़ आ गई थी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि खरगोन से सिरवेल क्षेत्र के बीच संचालित एक निजी यात्री बस को तेज बहाव के बीच पुलिया से निकाला गया। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। वहीं नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों के साथ पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षाकाल में जलमग्न होने वाली पुल-पुलियों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध और चेतावनी संबंधी सूचना पट्ट नहीं लगाए गए हैं। भगवानपुरा और झिरनिया क्षेत्र वनांचल होने के कारण यहां की पुलियाओं पर बाढ़ का पानी तेजी से आ जाता है।

भगवानपुरा थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लौवंशी ने बताया कि क्षेत्र में आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है। सिरवेल क्षेत्र में कोटवारों को निगरानी रखने के लिए सतर्क किया गया है। हालांकि उन्होंने अपने थाना क्षेत्र में उक्त बस के पुलिया पार करने की पुष्टि नहीं की।

## नुक्कड़ नाटकों से साइबर अपराधों के प्रति किया जा रहा जागरूक

**माही की गूंज, खरगोन।**

साइबर अपराधों की रोकथाम एवं जनजागरूकता के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक-2.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के आठवें दिन बुधवार सुबह जागरूकता रैली निकाली गई तथा दोपहर 11:30 बजे जिला रक्षित केंद्र में नागरिकों को डिजिटल सतर्कता के बिंदुओं पर शपथ दिलाई गई।

पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा के निर्देशन में जिलेभर में पुलिस दलों द्वारा विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं बाजारों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को साइबर अपराधों से बचने तथा किसी भी प्रकार के लालच में न आने का संदेश दिया जा रहा है। यह अभियान 8 जुलाई तक जारी रहेगा।

साइबर जागरूकता पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित नुक्कड़ नाटकों में डिजिटल गिरफ्तारी, फर्जी निवेश अनुप्रयोग, एपीके फाइल के माध्यम से व्हाट्सएप हैकिंग, फर्जी नकद वापसी एवं धनवापसी प्रस्ताव, फर्जी कॉल, फर्जी सामाजिक माध्यम प्रोफाइल, रोजगार ठगी, वैवाहिक वेबसाइट धोखाधड़ी तथा बैंकिंग एवं पेंशन संबंधी साइबर ठगी जैसे विभिन्न अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने, मजबूत कूटशब्द रखने, अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचने, संदिग्ध ई-मेल एवं संदेशों से सतर्क रहने तथा सामाजिक माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने की सलाह दी गई।

साइबर प्रकोष्ठ की टीम ने बताया कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी अथवा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल गृह मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

## जमीन विवाद में एसएएफ जवान और उसके भाई पर हमला, दोनों घायल

**माही की गूंज, खंडवा।**

पंधाना थाना क्षेत्र के टाकली मोरी गांव में मंगलवार सुबह खेत की बोवनी के दौरान जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हिंसक हो गया। हथियारबंद लोगों ने सशस्त्र पुलिस बल (एसएएफ) के एक जवान और उसके भाई पर धारदार हथियारों तथा लाठियों से हमला कर दिया। हमले में एसएएफ आरक्षक के सिर और उसके भाई की पसलियों में गंभीर चोटें आईं। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसएएफ आरक्षक धर्मेंद्र सोलंकी की पत्नी मनीषा सोलंकी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं। मनीषा ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि उनके पति और देवर अशोक सोलंकी मंगलवार सुबह खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान कुंवारसिंह, ठाकुरसिंह, बंजारी बाई, हेमंत तथा अन्य लोग वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मनीषा का आरोप है कि हमलावर 52 हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन तथा आवश्यक दस्तावेज भी अपने साथ ले गए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

मनीषा ने आरोप लगाया कि घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस अधीक्षक को शिकायत दिए जाने के बाद बोरगांव चौकी प्रभारी अविनाश भोपले अस्पताल पहुंचे और घायलों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने कुंवारसिंह, ठाकुरसिंह, नमजाबाई सहित पांच लोगों के विरुद्ध मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

विवादित जमीन को लेकर लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। मनीषा सोलंकी का कहना है कि उन्होंने उक्त जमीन खरीदी थी और न्यायालय ने उनके पक्ष में स्वामित्व का निर्णय दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने उन्हें जमीन का कब्जा भी दिलाया था, लेकिन दूसरा पक्ष लगातार खेती करने से रोक रहा है। इससे पहले 5 फरवरी को भी इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज किया था।

# लद्दाख की अस्मिता को निगलती पर्यटन संस्कृति

लेह प्रशासन बड़े गर्व से बता रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार लेह-लद्दाख में 44 फीसदी अधिक पर्यटक आए। हिमालय की गोद में बसा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख पिछले कुछ सालों में एक बड़े वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। हर साल गर्मी का मौसम आते ही यहां सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। पर्यटन ने प्रदेश की आमदनी में उल्लेखनीय इजाफा किया है। लेकिन इस आर्थिक समृद्धि के पीछे एक ऐसा स्याह सच भी छिपा है, जो लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी के लिए किसी गंभीर खतरे से कम नहीं है। विडंबना यह है कि जिसे कभी 'शांग्री-ला' यानी पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता था, वह आज अनियंत्रित पर्यटन के कारण उपजे कचरे, पानी की किल्लत, बिजली के संकट और वाहनों के धुएं से हांफ रहा है।

लेह-लद्दाख में लगभग 670 होटल बन गए हैं और इनमें से 60 फीसदी लेह शहर में हैं। चूंकि अधिकांश पर्यटक सबसे पहले लेह ही आते हैं और उन्हें कम से कम दो दिन वहीं रुकने की सलाह दी जाती है ताकि उनका शरीर वहां के परिवेश के अनुरूप खुद को ढाल सके, सो लेह पर वहां की मूल आबादी से तीन गुना बाहर से आए लोगों का बोझ सदा बना रहता है, जिनमें 50 हजार तो प्रवासी मजदूर ही हैं। जान लें इस इलाके में कहीं हरियाली दिखती नहीं। यह बर्फीला रेगिस्तान है। समुद्र तल से कोई 11 हजार फुट ऊपर बसे लेह में यहां सालाना बारिश मात्र 10 सेंटीमीटर होती है। लेह शहर में सिंधु नदी से पानी की आपूर्ति होती है लेकिन इतने सारे होटल बोरवेल पर निर्भर हैं।

लद्दाख इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। शीत मरुस्थल होने के कारण लद्दाख हमेशा से पानी के लिए ग्लेशियरों के पिघलने और सीमित बर्फबारी पर निर्भर रहा है। पारंपरिक रूप से लद्दाख के लोग शुष्क शौचालयों का उपयोग करते थे, जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन पर्यटकों की आधुनिक सुविधाओं और होटलों की मांग के कारण पारंपरिक व्यवस्था की जगह 'फ्लश टॉयलेट' ने ले ली है। एक स्थानीय लद्दाखी जहां गर्मियों में औसतन 21 लीटर पानी का उपयोग करता है, वहीं एक पर्यटक प्रतिदिन करीब 75 लीटर पानी सोख लेता है। लेह में होटलों और गेस्ट हाउसों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिन्होंने पानी की भारी मांग को पूरा करने के लिए अंधाधुंध कमर्शियल बोरवेल खोद डाले हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि लेह का भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है और प्रशासन को पानी की राशनिंग करने के साथ-साथ टैंकरों के जरिए जलापूर्ति करनी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण कम होती बर्फबारी और पर्यटन के अत्यधिक दबाव ने पानी की इस कमी को जीवन-मरण का प्रश्न बना दिया है।

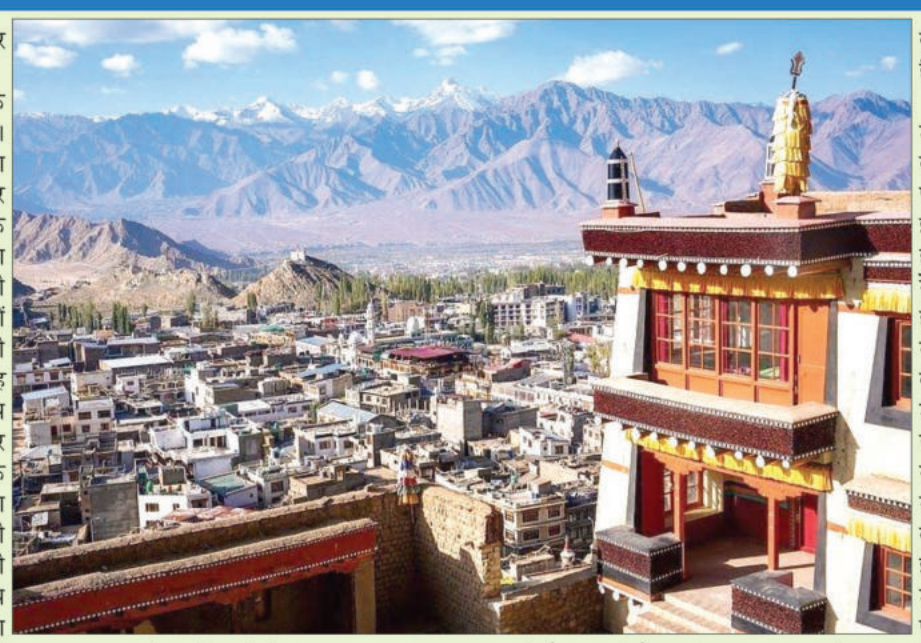

दरअसल, पर्यटन बढ़ने से हिमालय के पहाड़ों पर कचरे का संकट बढ़ता है। हालांकि अभी लेह प्रशासन ने समूचे इलाके में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के आदेश जारी किये हैं लेकिन अभी उसका कोई जमीनी असर दिख नहीं रहा। टूरिस्ट सीजन में लेह पर करीब 247 टन कचरे का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है। म्युनिसिपल कमेटी के अनुसार सर्दियों में कचरे की मात्रा गर्मियों की तुलना में सिर्फ 25 प्रतिशत ही रह जाती है। यह समस्या तब और विकराल हो जाती है जब लद्दाख की भौगोलिक ऊंचाई और कड़ाके की ठंड इसमें अड़चनें पैदा करती हैं। यद्यपि साल 2020 में स्कम्पारी में सौर ऊर्जा से संचालित 30 टन क्षमता का वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया गया है, लेकिन शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान में गीला कचरा पूरी तरह जम जाता है। अत्यधिक ठंड और ऊंचाई के कारण मजदूरों की कार्यक्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है, जिससे कचरे की प्रोसेसिंग में देरी होने लगती है। सबसे खराब स्थिति सर्दियों में भारी बर्फबारी के दौरान होती है, जब कचरा इकट्ठा करने वाले ट्रकों की आवाजाही ठप हो जाती है।

एक तरफ बढ़ते पर्यटक हैं और फिर उनकी सुविधाओं के लिए बिजली की मांग बढ़ती है वहीं लद्दाख के पास अपनी सीमित पनबिजली और सौर ऊर्जा प्रणालियां हैं, जो इस अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने में हांफने लगती हैं। गर्मियों में जब होटलों, रेस्टोरेंट्स और होमस्टे में पर्यटकों की भीड़ होती है, तब बिजली की मांग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। पीक सीजन में इस कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर डीजल जेनरेटरों का सहारा लिया जाता है। ये जेनरेटर न केवल भारी मात्रा में ईंधन की खपत करते हैं, बल्कि लद्दाख की शांत और स्वच्छ हवा में लगातार कार्बन और कानफोड़ू शोर घोलते रहते हैं। बिजली के इस अस्थायी और प्रदूषणकारी विकल्प ने शांत वादियों के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है।

इस पूरे संकट में वाहनों से निकलने वाला धुआं आग में घी का काम कर रहा है। पैंगोंग त्सो, नुब्रा वैली और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की यात्रा के लिए हर दिन सैकड़ों डीजल चालित एसयूवी, टैक्सियां और कमर्शियल गाड़ियां लेह की सड़कों से गुजरती हैं। इन जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के अनियंत्रित काफिलों के कारण लेह में न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो रही है, बल्कि इनसे निकलने वाला काला कार्बन (सूट) और धुआं हवा को प्रदूषित कर रहा है। यह काला कार्बन हवा में तैरकर आसपास के ग्लेशियरों पर जमा हो रहा है। ग्लेशियरों की सतह काली होने के कारण वे सूरज की रोशनी को परावर्तित करने के बजाय अधिक गर्मी सोख रहे हैं, जिससे उनके समय से पहले और तेजी से पिघलने का खतरा पैदा हो गया है। यह चक्र अंततः लद्दाख के पूरे जल विज्ञान और जीवन चक्र को नष्ट कर सकता है।

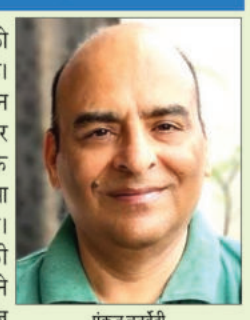

पंकज चतुर्वेदी

वर्तमान परिदृश्य में लद्दाख में पर्यावरण शुल्क जैसी नीतियां भी खामियों से भरी हैं, क्योंकि यह केवल लेह से बाहर जाने वालों के परमिट पर लागू होती हैं, जबकि सिर्फ लेह आकर प्रदूषण फैलाने वाले पर्यटकों से कुछ नहीं वसूला जाता। पर्यटन से होने वाली आमदनी का स्वागत है, लेकिन यह स्थानीय लोगों के जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। जब तक पर्यटक जिम्मेदार नहीं होंगे और प्रशासन कचरे, पानी, बिजली और वाहनों के धुएं के लिए एक एकीकृत मास्टर प्लान नहीं बनाएगा, तब तक इस नाजुक हिमालयी क्षेत्र को तबाही की तरफ बढ़ने से रोकना नामुमकिन होगा।

# रामघाट पर आरती के बीच बवाल

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले के प्रसिद्ध रामघाट पर मां शिप्रा की आरती के दौरान हुई मारपीट का मामला सामने आने के बाद धार्मिक नगरी की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आरती के बीच दो पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चलते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आरती में इस्तेमाल होने वाले दीपक और पूजा सामग्री का भी एक-दूसरे पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। महाकाल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 28 जून की है। रामघाट पर गणेश पिता शशिकांत शर्मा मां शिप्रा की आरती करा रहे थे। इसी दौरान घाट पर पूजन सामग्री बेचने वाली ममता परमार, शिप्रा मराठा और उनके कुछ साथी श्रद्धालुओं को सामान बेच रहे थे। आरोप है कि गणेश शर्मा ने आरती के दौरान सामग्री बेचने से मना किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई।

### आरती का सामग्री बेचने पर हुआ था विवाद

मारपीट के दौरान लात-घूंसों के साथ आरती के दीपक और अन्य पूजा सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया। घटना के समय घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। महाकाल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर अलग-अलग मामला दर्ज किया गया हैं। गणेश शर्मा की शिकायत पर ममता परमार और शिप्रा मराठा सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से उमा यादव की शिकायत पर गणेश शर्मा, विकास और उनके साथियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।

### भारी संख्या में मौजूद थे श्रद्धालु

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने रामघाट की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। आरती के समय अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। रामघाट पर प्रतिदिन सुबह और शाम मां शिप्रा की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की हिंसक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

# नहाते समय तालाब में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत

माही की गूंज, आम्बुआ।

थाना क्षेत्र के ग्राम कोटबू में मामा के घर आए दो बच्चों सहित मामा की एक मासूम बच्ची सहित तालाब में नहाने समय डूब जाने से तीनों की मौत की खबर ने ग्रामीण क्षेत्र कोटबू तथा काठी में शोक छा गया।

हमारे संवाददाता को थाना प्रभारी मोहन सिंह डावर ने बताया कि ग्राम कोटबू की वास्कल फलिया निवासी पप्पू के घर उसकी बहिन निवासी काठी अपने दो बच्चों को लेकर मेहमान आई है। दिनांक 30 जून को दोपहर लगभग 12 बजे तीनों बच्चे तालाब पर नहाने गए जहां पर नहाने के दौरान अज्ञात कारणों से तीनों गहरे पानी में डूब जाने से तीनों की मौत हो गई मृत बच्चों की उम्र 7,8,9 वर्ष बताई गई है। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी मय दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा सभी को बाहर निकाला गया जिनकी मौत हो चुकी थी शवों का पंचनामा बनाकर आलीराजपुर अस्पताल भेजा गया जहां पर शव परीक्षण किया जा कर परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सौंप दिया गया। इस आकस्मिक घटना से कोटबू सहित ग्राम काठी में मातम छा गया। थाना आम्बुआ में घटना की सूचना पर मार्ग कायम किया जा कर घटना से संबंधित जानकारी एकत्र कर जांच की जा रही है।

# रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक आयोजित

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर की अध्यक्षता में बुधवार को जिला रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक कलेक्टर कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा उपकरणों एवं विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा अस्पताल की सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की गई।

बैठक में जिला चिकित्सालय आलीराजपुर में विगत दो वर्षों के दौरान किए गए विकास कार्यों, गुणवत्ता सुधार गतिविधियों तथा मरीजों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. प्रकाश ढोके ने बताया कि जिला चिकित्सालय में एनक्यूएएस, लक्ष्य, मुस्कान एवं कायाकल्प कार्यक्रमों के अंतर्गत सतत गुणवत्ता सुधार गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल की सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपातकालीन (इमरजेंसी) यूनिट का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, नवीन मीटिंग हॉल का निर्माण एवं उन्नयन, मरीजों की सुविधा के लिए व्हीलचेयर स्टेशन की स्थापना तथा व्हीलचेयर की संख्या में वृद्धि की गई है। मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए आरओ सहित पांच वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त रक्त बैंक, एसएनसीयू, प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस यूनिट एवं अन्य विभागों में गुणवत्ता मानकों के अनुरूप आवश्यक निर्माण एवं सुधार कार्य किए गए हैं। अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 45 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए प्रत्येक पलंग पर सेंट्रल ऑक्सीजन प्वाइंट उपलब्ध कराए गए हैं। जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए किए गए विभिन्न कार्यों सहित रोगी कल्याण समिति की आय-व्यय का विवरण भी बैठक में प्रस्तुत किया गया।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश अतुलकर को निर्देश दिए कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों का अनावश्यक रेफरल रोका जाए तथा यथासंभव जिला चिकित्सालय में ही उनका समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला चिकित्सालय परिसर में पौधारोपण कर मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था विकसित करने, अस्पताल में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने तथा मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न होने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश अतुलकर, सिविल सर्जन डॉ. प्रकाश ढोके, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. दामिनी पटेल, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों सहित रोगी कल्याण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

# आरटीओ विभाग द्वारा स्कूल बसों की फिटनेस की कि जांच

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के निर्देशन में जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती कृतिका मोहटा द्वारा स्कूल बसों की फिटनेस जांच की गई। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा आज जोबट क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में संचालित बसों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान अंशुल विद्या मंदिर की एक स्कूल बस का फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त (एक्सपायर्ड) पाया गया, जिस पर मोटरयान अधिनियम के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं गायत्री शक्तिपीठ की दो स्कूल बसों का फिटनेस प्रमाणपत्र भी समाप्त पाया गया, जिन पर कुल 10,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इस प्रकार फिटनेस नियमों का उल्लंघन करने वाली कुल तीन स्कूल बसों पर 15,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।

जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती कृतिका मोहटा ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल वाहनों की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों से वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर अद्यतन रखने तथा परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की।

# पेप्सिको के फ्लेवर कंसनट्रेट निर्माण संयंत्र का लोकार्पण

माही की गूंज, उज्जैन।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मंगलवार को वीसी के माध्यम से उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी के ग्राम नरवर स्थित 1266 करोड़ रूपये लागत से निर्मित पेप्सिको फ्लेवर कंसनट्रेट निर्माण संयंत्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उज्जैन पहले धार्मिक नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध था, अब औद्योगिक विस्तार की नई इबारत लिख रहा है।

डॉ.यादव ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की इस अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई का शुभारंभ होने पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी । उन्होंने कहा कि भारत में इस विशिष्ट और उच्च तकनिकी फ्लेवर कंसनट्रेट निर्माण के केवल 2 संयंत्र है। जिनमें से 1 आज से उज्जैन में क्रियाशील हो रहा है। विक्रम उद्योगपुरी में 22 एकड़ क्षेत्र में 1226 करोड़ रु. के निवेश से इस संयंत्र की स्थापना की गई है। पूरी तरह ऑटोमेशन पर आधारित इस संयंत्र से 800 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। पेप्सिको द्वारा उज्जैन को चुनना यह प्रमाणित करता है की हमारी नीतियां अंतराष्ट्रीय स्तर की है । यह नया संयंत्र भारत में कंपनी की विनिर्माण क्षमता को और मजबुत करेगा।

कार्यक्रम में सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन, निगम सभापती कलावती यादव, संजय अग्रवाल, प्रबंध निर्देशक एमपीआईडीसी चंद्रमौली शुक्ला, एमपीआईडीसी उज्जैन के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर उपस्थित थे। कार्यक्रम में पेप्सिको इंडिया और साउथ एशिया के सीईओ जागृत कोटेचा ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का क्षण है की हमारी कंपनी को यहां प्रदेश शासन के सहयोग से संयंत्र स्थापित करने का अवसर मिला। शासन के प्रति हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते है। सांसद उमेंश नाथ महाराज ने कहा की उज्जैनवासीयों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिथि स्वागत पेप्सिको कंपनी के हरदीप भाटिया और राजेश राठौर ने किया। कंपनी के सीईओ इंटरनेशनल बेवरेजेस यूजीन विलेमसेन, जनरल मैनेजर एवं सीनियर वाईस प्रेसिडेंट इवान नॉर्टन उपस्थित थे।

## सड़क के बीचों-बीच बोरिंग

इंदौर।

मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। शहर के गिरधर नगर क्षेत्र में बीच सड़क पर कराई गई बोरिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरों को देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर सड़क के बीचों-बीच बोरिंग कैसे कर दी गई। इस मामले में स्थानीय पार्षद राजीव जैन का कहना है कि यह फैसला क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए लिया गया।

पार्षद राजीव जैन का दावा है कि सड़क के दोनों ओर गैस पाइपलाइन और सीवरेज लाइन होने के कारण कोई दूसरी जगह उपलब्ध नहीं थी। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी पार्षद के फैसले का समर्थन किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे लापरवाही करार दिया है।

सड़क के बीच बोरिंग को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन इंजीनियर था, जिसने बीच सड़क पर बोरिंग करवा दी। पहली नजर में यह व्यवस्था अजीब जरूर दिखाई देती है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई थी, जिसके समाधान के लिए यह कदम उठाया गया। पार्षद राजीव जैन ने कहा कि सड़क के एक ओर गैस पाइपलाइन है।

वहीं दूसरी तरफ सीवरेज लाइन होने की वजह से सुरक्षित जगह नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में तकनीकी स्थिति को देखते हुए सड़क के बीच बोरिंग करवाई गई। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्थानीय लोगों की सहमति से लिया गया है और जल्द बोरिंग के चारों ओर चौंबर बनाकर उसे सड़क के लेवल में व्यवस्थित कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी राहगीर या वाहन चालक को परेशानी नहीं होगी।

वहीं राजीव जैन ने कहा कि फिलहाल बोरिंग से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। जब इसे चौंबर के माध्यम से सड़क के अंदर समतल कर दिया जाएगा, तब राहगीरों को भी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।

वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के पार्षद और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सह प्रदेश प्रवक्ता हर्ष जैन का कहना है कि विकास कार्य केवल

किसी एक वर्ग की सुविधा को ध्यान में रखकर नहीं किए जाने चाहिए। सार्वजनिक सड़क पर होने वाले किसी भी निर्माण में आम नागरिकों और राहगीरों की सुरक्षा प्राथमिक होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि प्रशासन को ऐसे मामलों में तकनीकी मानकों का पालन करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। फिलहाल सड़क के बीच यह बोरिंग सोशल मीडिया पर चर्चा में है। देखना होगा कि नगर निगम और संबंधित विभाग इसे कितनी जल्दी स्थायी और सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित करते हैं, ताकि पानी की समस्या का समाधान भी बना रहे और सड़क की सुरक्षा भी प्रभावित न हो।

# बारिश पूर्व ग्रामीणों ने श्रमदान तथा अर्थ दान कर कर दिया कच्ची सड़क निर्माण

माही की गूंज, आम्बुआ।

कुछ करने का जज्बा यदि हो तो लोग पहाड़ को चीर कर भी रास्ता बना लेते है, ऐसा कुछ कारनामा कर दिखाया ग्राम भोरदू के ग्रामीणों ने जिन्होंने लगभग डेढ़ किलोमीटर कच्चा सड़क मार्ग बना डाला जबकि इस मार्ग के लिए आश्वासन मिलते रहे हैं।

हमारे संवाददाता को ग्राम भोरदू निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कमलसिंह कलेश ने बताया कि ग्राम वडी से भोरदू नाले तक एक पगडंडी मार्ग है जिस पर सड़क बनाने की मांग वर्षों से ग्रामीण करते आ रहे हैं, इन्हें आश्वासन भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनेकों बार मिलते रहे हैं।यह मार्ग पनवानी,वडी तथा भोरदू को जोड़ता है,इस मार्ग के बन जाने से उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनके खेत यहां है बारिश के समय कीचड़ हो जाने के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जब सब तरफ से ग्रामीण निराश हो गए तो उन्होंने स्वप्रेरणा से निर्णय कर आज दिनांक 29 जून को खुद के ट्रेक्टर आदि लगाकर मार्ग पर पत्थर मोरम आदि डालकर मार्ग निर्माण प्रारंभ किया है ताकि बारिश में कीचड़ तथा गड्ढों की परेशानी से बच कर खेतों तथा घरों तक पहुंचा जा सके। इस कार्य में कमलसिंह कलेश के अलावा जितेन रावत, रितेश कलेश अभयसिंह कलेश, अनिल रावत, गोलू कलेश, करदार रावत तथा दिलीप कलेश आदि का विषेश सहयोग मिल रहा है। इनका कार्य देख कर शायद शासन प्रशासन तथा क्षेत्रीय नेताओं का ध्यान आकर्षित होकि यह कार्य प्रमुखता के आधार पर कराया जाना चाहिए।

# थाने से हथकड़ी खोलकर फरार हुआ माफिया

इंदौर।

जिले के द्वारकापुरी थाने से एक आरोपी के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अवैध शराब के मामले में लंबे समय से वांटेड चल रहा एक आरोपी मंगलवार को पुलिस संतरी की आंखों में धूल झोंककर और चालाकी से हथकड़ी से अपना हाथ निकालकर थाने से भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद इंदौर पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी की घेराबंदी के लिए कई टीमें रवाना की गई हैं।

द्वारकापुरी थाना पुलिस ने सोमवार रात को अहीरखेड़ी इलाके के रहने वाले शातिर बदमाश साबिर उर्फ गज्जू को अवैध शराब के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। मंगलवार को थाने के भीतर उसे लोहे की बेंच से हथकड़ी लगाकर बैठाया गया था और सुरक्षा के लिए संतरी तैनात था।

इसी दौरान जब संतरी का ध्यान थोड़ा भटका, तो पतले हाथ या ढीली हथकड़ी का फायदा उठाकर साबिर ने चुपचाप अपना हाथ बाहर खींच लिया और पलक झपकते ही थाने के मुख्य दरवाजे से दौड़ लगा दी। जब तक संतरी और अन्य पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, आरोपी ओझल हो चुका था।

### बगल में बैठा था करोड़ों का ड्रग्स तस्कर

दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिस समय साबिर थाने में बैठा था, उसी के ठीक बगल में पुलिस द्वारा सोमवार को ही पकड़ा गया एक अन्य बड़ा और शातिर ड्रग्स तस्कर चेतन नाथ भी बैठा हुआ था। पुलिस की टीमें चेतन नाथ की भारी बरामदगी की कागजी कार्रवाई और जांच में व्यस्त थीं। थाने में मची इसी गहमागहमी और अफरा-तफरी का फायदा उठाकर साबिर उर्फ गज्जू भागने में कामयाब रहा।

### झोपड़ी से मिली नोट गिनने की मशीन

फरार आरोपी की तलाश के बीच द्वारकापुरी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल की है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि 22 जून को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए लकी नाथ नामक एक आरोपी ने पूछताछ में मुख्य सरगना चेतन नाथ का नाम उगला था।

इसके बाद पुलिस ने तस्दीक कर राजवाड़ा क्षेत्र से घेराबंदी करके मुख्य आरोपी चेतन नाथ को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस की टीम उसे लेकर राजेंद्र नगर और धार जिले के नौगांव थाने के मामलों से जुड़े उसके ठिकानों और घर पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों की आंखें फटी रह गईं। आरोपी के ठिकाने से 265 ग्राम ब्राउन शुगर, 8 किलो अवैध गांजा, 19 लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी, 22 जिंदा कारतूस और काले धन को गिनने के लिए रखी गई नोट गिनने की मशीन बरामद हुई।

### पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है पुलिस

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने मामले की तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी चेतन नाथ राजेंद्र नगर और धार जिले में भी कई मामलों में वांटेड चल रहा था। वह लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर और गांजा इंदौर में कहां से लाया जा रहा था और इस सिंडिकेट में कौन-कौन से रसूखदार लोग या पैडलर्स शामिल हैं। दूसरी ओर, थाने से हथकड़ी खोलकर भागे शराब आरोपी साबिर उर्फ गज्जू के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, साथ ही शहर के सभी नाकों पर नाकेबंदी कर उसकी तलाश तेज कर दी गई है।

# रोहित की संदिग्ध मौतः पुलिस ने दिया आत्महत्या करार तो परिजनों ने जताया विरोध, दिया ज्ञापन

अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुआ पंचाल समाज, एसपी को दिया ज्ञापन।

24 जून को रात्रि सवा 9 बजे के करीब रोहित ने अपनी बुलेट में देवीगढ़ चौराहे के करीब पेट्रोल पंप से भरवारा पेट्रोल।

आत्महत्या करार देने के बाद 30 जून मंगलवार को पूरे जिले के पंचाल समाज के प्रभुत्वजनों ने आक्रोश जताकर अंबेडकर पार्क झाबुआ में इकट्ठे हुए व आक्रोश रेली निकालकर एसपी कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे। एसपी कार्यालय पर एसपी ने ज्ञापन नहीं लेते हुए। ज्ञापन लेने एडिसनल एसपी रतिपाल सिंह महोबिया आए। एडिशनल एसपी ने समाजजनों को मामले में उचित जांच करने का आश्वासन दिया।

वही समाजजन एसपी से मिलने की जिद्द पर अड़े रहे। जिसके बाद एसपी के निर्देश में समाजजनों का प्रतिनिधि मंडल एसपी श्री पाटीदार से मुलाकात की तथा घटना के पूरे तथ्य एसपी के सामने रखें। समाजजनों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा एसपी को बताया गए तथ्यों को मजबूत तथ्य होना एसपी ने बताया। तथा 1 सप्ताह के अंदर मामले तक पहुंचने की बात कह कर एसपी ने आश्वासत किया। वहीं एसपी के निर्देशन में एसडीओपी के नेतृत्व में उक्त मामले हेतु जाँच टीम गठित की गई।

माही की गूंज को परिजनों ने बताया कि, पुलिस, मोबाइल डिटेल के साथ समाजजनों के बताएं तथ्यों जो घटना स्थल के आस-पास हत्या होने के साक्ष्य हैं उन्हें गंभीरता से उच्च स्तरीय जांच में लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो इस संदिग्ध हत्या का खुलासा अवश्य हो सकता है।

**माही की गूंज, काकनवानी।**
**नरेश पंचाल**

मामला कितना भी बड़ा संदिग्ध हो लेकिन पुलिस मामले को सामान्य मान ले तो उसका कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। बाद में आखिरी एक ही हल निकल कर आमजन के सामने आता है वह है प्रदर्शन व विरोध। यानीकि अब पुलिस की मनमानी व निठलेपन के चलते अब आमजन को न्याय मांगने हेतु प्रदर्शन व विरोध करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

पुलिस के निठलेपन का एक नजारा समाजजनों के प्रदर्शन व एसपी कार्यालय में ज्ञापन के रूप में मंगलवार को भी सामने आया है। जिसमें जिस मामले में पुलिस आत्महत्या करार दे रही थी लेकिन पंचाल समाज एवं आमजनों ने युवक की हत्या होने संबंधी तमाम प्रमाण दिए जो घटना स्थल व आस-पास दिखाई दे रहे हैं।

मामला यह कि, काकनवानी निवासी एवं कियोस्क संचालक रोहित पिता बाबूलाल पंचाल (35) 24 जून को देर शाम करीब पौने 8 बजे घर से खाना खाकर बाजार में जा रहा हूं कहकर अपनी बुलेट बाईक लेकर निकला। लेकिन 5 घंटे बाद करीब 1 बजे पुलिस से सूचना मिलती है कि, नागनवाड़-रम्भापुर मार्ग पर पाट नदी के पुल के ऊपर बाबूलाल जी पंचाल के नाम से दर्ज बुलेट बाईक खड़ी हुई है तथा एक व्यक्ति पुल के नीचे नदी में मृत पड़ा हुआ है। जैसे ही उक्त सूचना रोहित के परिजनों को मिली, वैसे ही रात्रि में पंचाल समाज के कुछ व्यक्ति व गांव के आमजन काकनवानी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाट नदी पर पहुंचे जहां बुलेट बाइक नदी के पुल के ऊपर खड़ी मिली। साथ ही रोहित के पहने चप्पल भी पुल के ऊपर ही मिले। रोहित का शव पुल से करीब 70 से 80 फीट नीचे सुखी नदी के सेंटर में पत्थर की चट्टान के ऊपर उन्दे मुंह पेट के बल शव मिला। वही रात्रि में ही पुलिस ने रोहित की मौत को आत्महत्या करार दे दिया था तो परिजनों के हाल-बेहाल हो गए थे। रात्रि में शव को मेघनगर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था।

हसमुख मिजाज का रोहित बाजार में जाने का कहकर आखिर किस रास्ते से होकर मेघनगर से रम्भापुर होते हुए पाट नदी पर पहुंचा।

मौके पर प्रथम दृष्टिया ही शव का परीक्षण करने पर सामने आया कि, रोहित की पीठ पर किसी बेल्ट या लट्ठ से पीटा गया हो उसके निशान भी दिखाई दिये। वहीं रोहित की नाक में से खून निकला दिखाई दिया। 70 से 80 फीट नीचे अगर रोहित कुदता तो तय है पथरीली चट्टान पर गिरने से सिर से लेकर पेर तक हड्डियों का कचूमर जरूर बन जाता लेकिन पेर से लेकर मुंह व सिर तक किसी प्रकार की हड्डी टूटी हुई नहीं मिली। व न ही किसी प्रकार की गहरी चोट गिरने जैसी शरीर के किसी भी अंग पर दिखाई दे रही है।

वही मेघनगर/रम्भापुर पुलिस मंगलवार 30 जून तक ज्ञापन देने के पूर्व तक रोहित की संदिग्ध मौत को आत्महत्या ही बताती रही। जिसके बाद पुलिस की मनमानी व हठधर्मिता के चलते जहां रोहित की मौत को आत्महत्या बताकर किसी प्रकार की कोई फोरेंसिक रिपोर्ट न बनाई गई न ही कोई खोजी डॉग को लाया गया। वहीं दूसरी ओर परिजनों व स्थानीय लोगों को रोहित की मौत आत्महत्या नहीं होकर हत्या होना प्रतीत होकर शंका जताकर घटना के आस-पास जब दस्दीक की गई। तो सामने आया कि, घटना स्थल से करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर गाड़ियों की आड़ में पत्थरों व जमीन पर खून मिला। वही झाड़ पर भी खून के निशान दिखाई दिये। तथा बुलेट बाईक के टायर के निशान भी खून के आसपास नीचे दिखाई दिए। वही बुलेट की चाबी शव से कुछ दूरी पर मुडी हुई मिली। यह तथ्य दर्शाते हैं कि रोहित की आत्महत्या नहीं हत्या हुई है।

वही हमारा भी मानना है कि, पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर जांच करेगी तो यह मामला हत्या के रूप में सामने आएगा। क्योंकि कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इतनी दूर अपने क्षेत्र को छोड़कर आत्महत्या करने के लिये नहीं जाएगा? तथा कोई भी गुस्से में आकर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने चप्पलों को पैरों से निकालने के बाद कूदकर आत्महत्या नहीं करेगा?

### परिजनों के सामने यह भी तथ्य आए सामने

जहां पुलिस ने एक सिरे से रोहित की मौत को आत्महत्या करार दे दिया था वही परिजन व स्थानीय लोगों ने जो कार्य पुलिस को करना चाहिए था वह किया। जिसमें घटना स्थल व आस-पास का निरीक्षण किया जहां हत्या जैसे कई तथ्य सामने आए। वहीं परिजन व आमजन ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस के अनुसार साढ़े 11 बजे गस्त के दौरान पाट नदी के पुल पर खड़ी बुलेट व चप्पल दिखाई दिए। रोहित घर से पौने 8 बजे के करीब निकला और साढ़े 11 बजे रम्भापुर पाट नदी पर मिली बाईक के साथ मौत की पुष्टि होने के साथ करीब पौने 4 घंटे कहां रहा और कहां पर गया होगा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जिसमें सामने आया कि, सवा 9 बजे के करीब टोल के आगे थांदला की और देवीगढ़ चौकड़ी के पास पेट्रोल पंप पर 200 रुपए का पेट्रोल बुलेट में भरवाया। वहीं करीब 10 बजकर 20 मिनिट पर रम्भापुर में स्थित बाबजी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में सामने आया कि, रोहित मेघनगर की ओर से आते हुए बुलेट बाइक से दिखा। वहीं 1 घंटे 10 मिनट बाद करीब साढ़े 11 बजे पुलिस को पाट नदी पर रोहित की बुलेट दिखी। यानी इसी 1 घंटे 10 मिनट के दरमियान हीं रोहित की हत्या किया जाना सामने आ रहा है।

हत्या जैसे तमाम तथ्यो के बावजूद पुलिस द्वारा

घटनास्थल से कुछ दूरी पर बुलेट की मुड़ी हुई चाबी, 200 से 300 मीटर की दूरी पर नीचे जमीन पर व पत्थर पर मिला खून व बुलेट बाइक के टायर के निशान।

सुखी पाट नदी में पत्थर की चट्टान पर उन्दे मुंह पेट के बल पड़ा मिला रोहित का शव, शव के आस-पास 200 से 300 मीटर दूरी पर जो मिट्टी देखी गई वह भी मिली।

# कलेक्टर के आदेशों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां, दोषी कौन...?

## नियम, कानून को ताक में रखकर प्रतिबंध के बावजूद शहर में प्रवेश कर रहे भारवाहक वाहन

**माही की गूंज, झाबुआ।**

जब-जब अधिकारियों के आदेशों को पलीता लगता है या उन आदेशों का माखौल उड़ाकर आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तब-तब यह स्पष्ट हो जाता है कि, या तो अधिकारी में दम नहीं है या फिर जारी आदेश सिर्फ और सिर्फ कागजी पुलिंदा हैं। जिसके जारी होने से घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। या फिर अधिकारी सिर्फ आदेश जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री करते हैं। क्योंकि पिछले अधिकारियों के आदेशों की हूबहू कॉपी कर नए अधिकारी भी आदेश को महज औपचारिकता समझकर जारी कर रहे हैं। ऐसे कई आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं, जिनका कोई औचित्य या असर जिले में दिखाई नहीं देता। मगर परंपरा अनुसार हर साल या समय आने पर इस तरह के आदेश आंखें बंद कर जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रीष्मकाल में पानी की किल्लत का हवाला देकर बोरिंग या नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वर्षा ऋतु आने पर मत्स्याखेट पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जो साल भर में पिछले आदेशों की कॉपी मारकर जारी कर दिए जाते हैं। इसी तरह की फेहरिस्त में एक और आदेश नगर में भारवाहक वाहनों के प्रतिबंध का आदेश भी अब जुड़ चुका है। हालांकि इस आदेश की हालत भी ऐसी ही है जैसी नलकूप खनन या मत्स्याखेट प्रतिबंधात्मक आदेश की होती है। आदेश जारी होते हैं, मगर इन आदेशों पर अमल हो रहा है या नहीं, इसे देखने वाला कोई नहीं है। कुल मिलाकर जिला प्रशासन इस तरह के आदेशों को जारी कर पूरी तरह से औपचारिकता निभाता ही दिखाई देता है।

शहर में हो रही वाहन दुर्घटनाओं और

सुबह प्रतिबंधित समय में हुई उत्कृष्ट स्कूल के पास बड़ी दुर्घटना, कोई जनहानी नहीं।

जनहानि को देखते हुए पूर्व कलेक्टर नेहा मीणा ने लगभग एक वर्ष पूर्व आदेश जारी कर शहर में भारी मालवाहक वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि इस आदेश में भी पूर्व कलेक्टर ने अदूरदर्शिता का परिचय दिया था और कई तरह की परेशानियों का सामना आमजन को करना पड़ा था। कलेक्टर मैडम अपने अड़ियल रवैये पर इतनी सख्त थीं कि महज दो माह में ही जिला प्रशासन ने उनके इस आदेश को चार से पांच बार अक्षरशः रिपीट कर दिया था। बस, यहीं से एक और आदेश परंपरा का हिस्सा बन गया। पूर्व कलेक्टर नेहा मीणा के जाने के बाद भी अब जिला प्रशासन उसी आदेश को अक्षरशः रिपीट करते हुए नए कलेक्टर के आदेश बताते हुए जारी कर रहै है। पूर्व कलेक्टर नेहा मीणा ने स्थितियों को देखते हुए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए थे, लेकिन कुछ ही समय में स्थितियां ढाक के तीन पात साबित हुईं। पिछली 18 जून को जिला प्रशासन ने फिर से वही आदेश अक्षरशः कॉपी-पेस्ट करते हुए वर्तमान झाबुआ कलेक्टर योगेश तुकाराम भरसट द्वारा जारी कर दिया। इस आदेश की भी हकीकत ढाक के तीन पात ही साबित हुई। क्योंकि इस तरह के आदेश जारी होने के बावजूद न तो शहर में भारवाहक वाहन प्रतिबंधित हुए और न ही यातायात पुलिस का अमला इसे रोक पाने में सफल रहा। शहर के ट्रांसपोर्टर पहले ही इस आदेश की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। जिन्हें व्यापारियों और व्यापारी संघ का संरक्षण मिलता ही रहा है।

व्यापारी संघ के पदाधिकारी अक्सर अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर दबावपूर्वक भारवाहक वाहनों को शहर में घुसेड़ ही लाते हैं। अधिकारियों से चर्चा के बाद यातायात अमला भी इन ट्रांसपोर्टरों के आगे नतमस्तक हो जाता है। आदेशों में जो सीमा तय की गई है, उसके बाहर केवल वही भारवाहक वाहन खड़े रहते हैं, जिनके पास कोई जुगाड़ या जरिया न हो। बाकी के जुगाड़ लगाकर शहर की सीमाओं में घुस ही आते हैं। जब कलेक्टर के आदेशों की चारों तरफ से धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो फिर परिणाम नगर की आम जनता को ही भुगतना पड़ते हैं।

बुधवार के दिन कुछ इसी तरह से आदेशों की धज्जियां उड़ाता दिखाई दिया। जिसने कलेक्टर के आदेशों की हवा निकाल दी और यातायात पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। घटनाक्रम कुछ ऐसा था कि, बुधवार सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच एक भारवाहक ट्राला शहर में प्रवेश करता है। ट्रक में क्षमता से अधिक और भारी माल भरा होने के चलते वह जब बस स्टैंड के छतरी चौक से होता हुआ हायर सेकेंड्री स्कूल की चढ़ाई पर पहुंचता है तो क्षमता से अधिक माल भरा होने और ड्राइवर द्वारा ट्राले से संतुलन खो बैठने के कारण वाहन चढ़ाई से पीछे की ओर लुढ़क गया। जब चढ़ाई से वाहन रिवर्स हुआ तो ड्राइवर पूरी तरह से वाहन से नियंत्रण खो बैठा। रिवर्स होता हुआ भारी-भरकम ट्राला सज्जन रोड पर बने डिवाइडर पर चढ़ गया और बिजली के खंभे तोड़ता हुआ वहीं रुक गया। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि, अगर यही दुर्घटना स्कूल के लगने या छुटने के समय होती तो किसी बडी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था। दूसरा यह कि, अगर वाहन डिवाइडर या बिजली के पोल से नहीं टकराकर रुकता तो वह सीधा सज्जन रोड पर बने कॉम्प्लेक्स की दुकानों में जा घुसता, जिससे भी बड़े नुकसान की आशंका थी।

अब बात करते हैं कलेक्टर द्वारा शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रतिबंध की तो आदेशानुसार नगर में सुबह सात बजे के बाद से भारी मालवाहक वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित किए गए हैं। बावजूद इसके यह भारी मालवाहक वाहन शहर में कैसे पहुंच गया। जबकि आदेशों के अनुसार शहर की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही इन्हें रोके जाने के आदेश हैं। शहर से मेघनगर की तरफ जाने वाले रास्ते पर तीन किलोमीटर दूर करड़ावद हनुमान मंदिर पर बाकायदा इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है और यहां यातायात जवानों की ड्यूटी होती है। दूसरी तरफ शहर से इंदौर की तरफ जाने वाले रास्ते पर गड़वाड़ा में पारा फांटे पर भी ऐसी ही व्यवस्था बनाई गई है। शहर से आलीराजपुर जाने वाले रास्ते पर टंट्या भील चौराहे पर भी यही व्यवस्था है, जहां से भारी मालवाहक वाहन शहर में पूर्ण रूप से सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंधित हैं। बावजूद इसके शहर में इस तरह के भारी मालवाहक वाहनों का दिखाई देना आदेशों और व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े करता नजर आ रहा है।

इसी तरह का एक और घटनाक्रम इसी घटनास्थल के करीब छतरी चौक पर दोपहर करीब 12 बजे भी देखा गया। ट्रांसपोर्ट का सामान भरा एक और भारी मालवाहक वाहन बेधड़क अपनी सीमाओं को लांघता हुआ ठेठ बस स्टैंड के समीप छतरी चौक तक पहुंच जाता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। छतरी चौक पर यातायात जवान इस वाहन को रोकता है। ड्राइवर से वाहन वापस ले जाने पर बहस करता है। ड्राइवर एक फोन घुमाता है और यातायात जवान के हाथ में थमा देता है। मगर सुबह हुई दुर्घटना को देखते हुए यातायात जवान कोई रिस्क न लेते हुए फोन पर कहा-सुनी कर फोन फिर से ड्राइवर को दे देता है। इसी बीच बस स्टैंड से निकलने वाली बस और बस स्टैंड की ही तरफ से एक आयशर वाहन भी आ जाता है। मशक्कत के बाद यातायात जवान अपने सहकर्मी के साथ मिलकर स्थिति को संभालता है और भारी मालवाहक वाहन को पलटाकर रवाना करता है। जिसके बाद यातायात सामान्य हो पाया।

सुबह हुई दुर्घटना के बावजूद दोपहर १२ बजे इस तरह शहर के छतरी चौक पर कैसे घुस आए भार वाहक वाहन?

अब सवाल यह कि, आखिर प्रतिबंध के बावजूद शहर में घुसे और दुर्घटनाग्रस्त हुए इन वाहनों के चालान तक भी क्यों नहीं काटे गए? बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के इन वाहनों को क्यों जाने दिया गया? क्या जिले में कलेक्टर के आदेशों की कोई अहमियत नहीं है? क्या इस तरह के आदेश केवल अक्षरशः कॉपी कर जारी करने भर के लिए हैं? या फिर इन पर अमल भी होता है? हालांकि इसकी हकीकत शहर का हर नागरिक जानता है कि, इस तरह के आदेशों पर कितना अमल हो रहा है। या फिर यातायात अमला कलेक्टर के इस तरह के आदेशों को जूते की नोक पर रखता है? यातायात अमले के वे जवान कहां हैं, जिनकी ड्यूटी इस तरह के वाहनों को रोकने के लिए शहर के बाहर लगाई गई थी? या फिर खेल कुछ और ही है। बुधवार को हुई दुर्घटना के बाद जनचर्चा का विषय तो यह भी है कि क्या इन वाहनों को शहर में घुसने के लिए एंट्री लेकर छोड़ दिया जाता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। इन सवालों के जवाब हों या न हों, लेकिन एक बात जो साफ-साफ दिखाई दे रही है, वह यह कि जिले में कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। चाहे फिर वह उनका अपना आदेश कॉपी-पेस्ट करने वाला अमला हो, पुलिस या यातायात पुलिस का अमला हो या फिर ट्रांसपोर्टर्स।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422